Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume - 09 Issue - 09 July - 2026
Total Pages - 40 Price - Rs. 100

Udyam Yatra
Sushil Kumar Bahety
Leading Entrepreneur
West Bengal

New Safeguards

Amendment Bill for the MSME Sector

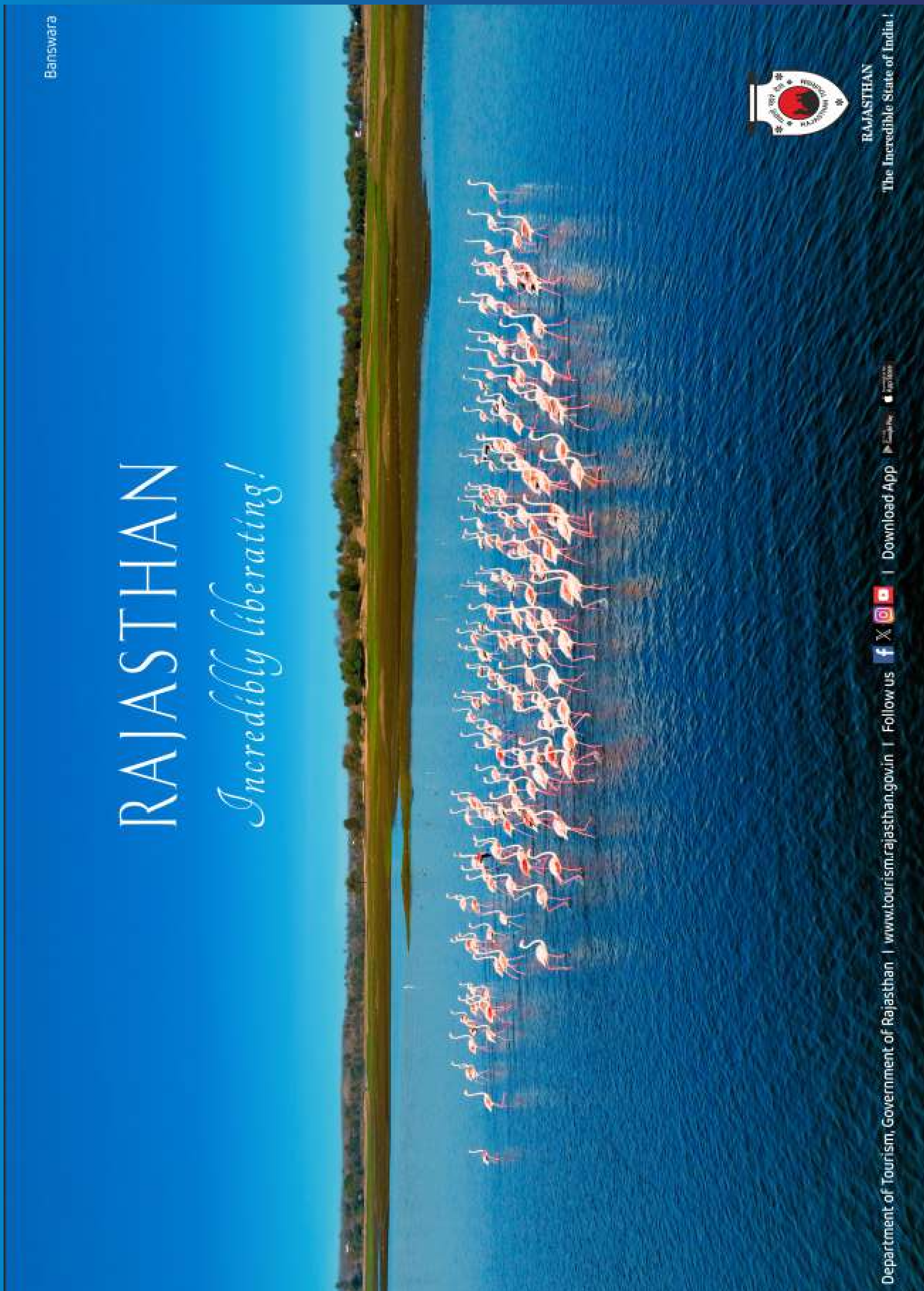
Banswara
RAJASTHAN
Incredibly liberating!
RAJASTHAN
The Incredible State of India!
Department of Tourism, Government of Rajasthan | www.tourism.rajasthan.gov.in | Follow us | Download App

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -9 Issue - 9 July 2026

Editorial Board

■ *Patron*

Shri Madhusudan Dadu, National President	098102-56494
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

■ *Editor*

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

■ *Co-Editor*

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	03
Bhumi Pujan for Skill Centre at Gandhinagar	04
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के निहितार्थ	05
MSME Bill, 2026	11
Udyam Yatra	15
पाली के स्वरोजगार प्रकल्प	18
राजस्थान में विकास के नए अध्याय	19
LUB Pharma Conclave-2026	21
Industry-Academia	25
Roorkee Industry Dialogue	27
LUB's News in Brief	29

Important Notice : As per Board Resolution passed in the meeting of Board of Directors of Laghu Udyog Bharati held on 24.04.2026 at Jaipur, Shri Madhu Sudan Dadu, All India President of Laghu Udyog Bharati has been appointed as publisher of Udyog Time, a bilingual National Monthly Magazine with immediate effect.

Annual Membership: Rs. 1200 Including Postage

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582
Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

MSME Amendment Bill will Strengthen the Institutional Framework

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill 2026 -- passed by Parliament -- will strengthen the institutional framework, enhance regulatory flexibility and ease operational constraints for MSMEs, LUB thinks so.

The Bill also relates issues relating to the ease of doing business through decriminalisation, provides institutional mechanisms for promotion of MSMEs, and addresses payment delays faced by the Micro and Small Enterprises.

The bill will strengthen the overall ecosystem for the speedier growth of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector in the country.

The Act, will provide greater regulatory flexibility, with stronger mechanisms to various operational concerns of industries.

The statutory recognition of digital Udyam registration and the revised classification framework will provide a more predictable basis for enterprises to scale creating more employment opportunities through the MSME sector.

These measures will support the transition of MSMEs from small operations towards more formal, productive, and scalable enterprises. The provision for mandatory routing of CPSEs' invoices through TReDS will further ease the liquidity and all these measures will reduce working-capital pressures, improve cash-flow predictability and enable MSMEs to deploy more resources towards investment, employment and business expansion.

It mandates that in the case of disputes mediation must be completed within 90 days and requires courts to release at least 50 per cent of disputed awarded amounts to MSMEs if an appeal lingers past six months.

❑❑❑

Bhumi Pujan Ceremony for Skill Centre held at Gandhinagar

New Initiative

Mehul Jadav
Karnawati District General Secretary
Laghu Udyog Bharati, Gujarat
mehulpjadav1980@gmail.com

Under the joint auspices of Laghu Udyog Bharati, Gujarat and Industry Development Council, the grand Bhumi Pujan ceremony of the proposed 'Skill Development Centre was conducted at the Electronics GIDC campus located at Sector-25, Gandhinagar on 16th July, 2026.

The sacred ceremony of the groundbreaking and foundation stone laying was performed with chanting of Vedic mantras and rites in the dignified presence of Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Bhai Patel, All India Convener Pujya Swami Parmanand Saraswati Ji, LUB's National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra Ji, Gujarat Pradesh Sangh Chalak Dr. Bharat Bhai Patel, former National President Shri Vajubhai Vaghasiya, and Shri Baldev Bhai Prajapati, State President Shri Ishwar Bhai Patel and State General Secretary Shri Hansraj Bhai Gajera.

This modern skill development centre will provide industry-oriented training to the youth of Gujarat's MSME sector in emerging fields such as semiconductors, information technology, digital technology, and advanced manufacturing. At the same time, this centre will play an important role in giving new direction and momentum to the Government of India's 'Skill India' campaign.

On this occasion, the major donors who contributed to the building construction were also honored. The program was attended by officials of Laghu Udyog Bharati, people's representatives, industrialists, entrepreneurs, and many distinguished citizens. The 'Skill Development Building' will prove to be a powerful centre for modern technical training, industry-friendly skill development, and job creation for Gujarat's MSME sector, and will make a significant contribution to realizing the resolve of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat @ 2047.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के निहितार्थ

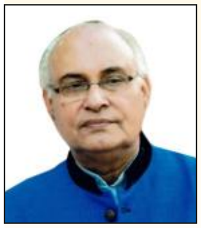

अंतर्दृष्टि

डॉ. महेश शर्मा

अध्यक्ष, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

mahesh.chandra.sharma@live.com

"यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे। यह बात बिलकुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक–राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे। हमारा रहन–सहन एक था। तभी तो अंग्रेजों ने यहां एक राज्य कायम किया, जिन दूरदर्शी पुरुषों ने सेतुबंध रामेश्वर, जगन्नाथ पुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय में क्या ख्याल होगा? वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिये।"

हिन्द स्वराज में प्रकाशित महात्मा गांधी का ये उद्धरण इस बात का द्योतक है कि वे भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ही प्रवक्ता थे। आजादी के बाद पाश्चात्य राष्ट्र राज्य अवधारणा ने भ्रम उत्पन्न किया। दीनदयाल उपाध्याय ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक अवधारणा के रूप में विवेचित किया। इस आलेख में हम राष्ट्र–अवधारणा की पड़ताल करेंगे।

राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद इन शब्दों का आज विश्व साहित्य में खूब उपयोग होता है। राजनीति एवं विचारधाराओं के साहित्य में इनकी परिभाषाओं को लेकर भी बहुत कुछ लिखा गया है। दुनिया भर में राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के नाम पर चलने वाले आंदोलन काफी भाव–प्रवण एवं उत्तेजक होते हैं। परन्तु तथ्यतः आज राष्ट्र शब्द की परिभाषा में घोर अराजकता है तथा व्यवहारतः संयुक्त राष्ट्र संघ जिस किसी भी संप्रभु राज्य को 'राष्ट्र' की मान्यता दे देता है, वह राष्ट्र कहलाता है। इस मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई मानक परिभाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी संप्रभु राज्य को यह मान्यता देता है। इसलिए विश्व में 'राष्ट्रों की संख्या घटती–बढ़ती रहती है।

यूरोप में राष्ट्रवादः

वस्तुतः राष्ट्र तत्य की यह दुर्दशा, तब हुई जब यूरोप में 'राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं... रोम के साम्राज्यों के पतन के बाद रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति विद्रोह अथवा उसके प्रभाव में कमी के कारण यूरोप में राष्ट्रों का उदय हुआ।

यूरोप का पिछले एक हजार वर्ष का इतिहास इन राष्ट्रों के आविर्भाव तथा परस्पर संघर्ष का इतिहास है। इन राष्ट्रों ने यूरोप महाद्वीप के बाहर जाकर अपने उपनिवेश बनाए तथा दूसरे स्वतंत्र देशों को गुलाम बनाया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण राष्ट्र और राज्य की एकता की प्रवृत्ति भी बढ़ी तथा राष्ट्रीय राज्य का यूरोप में उदय हुआ। साथ ही रोमन कैथोलिक चर्च के केन्द्रीय प्रभाव में कमी हो कर या तो राष्ट्रीय चर्च का निर्माण हुआ। मजहब का और मजहबी गुरुओं का राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। सेक्युलर स्टेट की कल्पना का इस प्रकार जन्म हुआ।'

राष्ट्रवाद के संदर्भ में पश्चिम की दृष्टि न केवल राजनीतिक वरन् नकारात्मक भी रही। दीनदयाल जी लिखते हैं "कुछ लोग राष्ट्र कल्पना को ही नकारात्मक मानते हैं भावात्मक नहीं।..... इंग्लैण्ड पर जब हमला हुआ, तो राष्ट्रवाद जागृत हुआ। एक अंग्रेजी कहावत है "Nations die in peace and live in war" अर्थात् शांतिकाल में राष्ट्र मर जाते हैं युद्धकाल में जीवित रहते हैं।..... हमारा राष्ट्र जीवन जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, यदि इसका आधार विरोध, युद्ध या विपत्ति ही हो, तो यह ठीक नहीं है। हम भावात्मक आधार पर खड़े हैं। जीवन की एक दृष्टि हमारे सामने है। हम संसार में पैदा हुए है, तो किसी का विरोध करने के लिए नहीं। हमारे सामने एक महत्वपूर्ण विचार है कि हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं।" दीनदयाल जी कहते हैं यह जोड़ने वाला विचार हमारी संस्कृति है तथा यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मर्म है।

पश्चिम के राष्ट्रवाद ने अनेक व्यावहारिक एवं परिभाषागत समस्याएं खड़ी की हैं, लेकिन पश्चिम के विद्वानों ने जो राष्ट्रवाद पर बहस चलायी है, वह पढ़ने योग्य एवं पर्याप्त ज्ञानवर्धक है। इस बहस में भांति–भांति के राष्ट्रवादों की चर्चा है यथा मानवतावादी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय राज्य, नस्लवादी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता–बहुल संघ राज्य, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, संवैधानिक राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्रीय राष्ट्रवाद आदि। इन व्याख्याओं को आक्रामक एवं उदार राष्ट्रवाद की संज्ञाओं में वहां विभक्त किया है। इस संदर्भ में विलियम एबेन्सटाइन का यह कथन उद्धरणीय हैः

''अट्ठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर, उन्नीसवीं सदी के मध्य तक राष्ट्रवाद मानववादी तथा लोकतंत्र वादी विचारों से सम्प्रेरित था। यह फ्रेंच, अमेरिकन, चेक, इटैलियन, आयरिश तथा पोलिश राष्ट्रवाद के प्रारंभिक दिनों की कहानी है। इसके विपरीत पिछले अस्सी सालों में राष्ट्रवाद अब पृथकतावाद, असहिष्णुता, कट्टरता, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, नस्लवाद और अंततः साम्राज्यवाद व आक्रमणों से सम्बद्ध हो गया है। अखिल जर्मनवाद, जारवादी साम्राज्य, जापानी सैन्यवाद, फासीवाद और अब साम्यवादी साम्राज्य इसी बात के प्रमाण हैं।''

राष्ट्रवाद की यह बहस राष्ट्र के संस्कृति अधिष्ठान की भी पर्याप्त चर्चा करती है। मैजिनी ने राष्ट्रवाद के 19 सूत्र लिखे हैं। इनमें सत्रहवां सूत्र हैः

''प्रत्येक जन का अपना जीवन लक्ष्य होता है। सामान्यतः स्वीकृत मानवीय जीवन लक्ष्य की सम्पूर्ति में जो सहयोगी होता है, वह जीवन लक्ष्य ही उसकी राष्ट्रीयता का निर्माण करता है। राष्ट्रीयता पवित्र होती है।" मैजिनी के आदर्शवादी राष्ट्रवाद की उनके स्वयं के ही देश इटली में उद्भूत 'फासीवाद' ने बड़ी बेरहमी से धज्जियां उड़ा दी।

फ्रांसीसी विद्वान अर्नेस्ट रीनाँ राष्ट्र की नस्ल, भाषा, मजहब, भू–क्षेत्र एवं वर्गीय हित सम्बंधी अवधारणाओं का खण्डन

करते हुए कहते हैं "राष्ट्र एक आध्यात्मिक सार तत्व है। इसके दो मुख्य तत्व हैं समृद्ध परंपरा की स्मृतियों का साझापन तथा समझौते पूर्वक साथ रहने और जीने की बलवती इच्छा। ये तीनों परिभाषाएं दीनदयाल उपाध्याय के 'चिति' तत्व का समर्थन करती हैं। अपने 'सिद्धांत व नीति' प्रलेख में वे कहते हैं, "प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशेष प्रकृति होती है, जो ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक कारणों का परिणाम नहीं अपितु जन्मजात है। इसे चिति कहते हैं। राष्ट्रों का उदयावपात चिति के अनुकूल अथवा प्रतिकूल व्यवहार पर निर्भर करता है। चिति स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा व्यक्तियों को पुरुषार्थ के ''सम्पादन की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए अनेक संस्थाओं को जन्म देती है – जाति, वर्ण, पंचायत, संघ, विवाह, संपत्ति, राज्य आदि इसी प्रकार की संस्थाएं हैं।"

यूरोपीय विद्वानों की राष्ट्रवाद विषयक परिभाषायें भी तत्वतः संस्कृति मूलक हैं, लेकिन 'राष्ट्र राज्य' की परिस्थिति ने इसे फासीवाद व नाजीवाद से जोड़ दिया। 'राष्ट्र राज्य' अवधारणा ने यूरोप को बाँटा, युद्ध नियोजित किए तथा उपनिवेशवाद का वैश्विक अध्याय रचा। इस पर टिप्पणी करते हुए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि पाश्चात्य राष्ट्रवाद विश्व–शांति का दुश्मन बन गया।

भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवादः

वस्तुतः राष्ट्र–राज्य की स्थापना के पूर्व राष्ट्र सांस्कृतिक इकाइयां ही थीं। आज भी अरब राष्ट्रवाद की बात होती है, यूरोपीय राष्ट्रवाद की भी चर्चा होती है अफ्रिकन राष्ट्रवाद का नारा बुलंद होता है, वैसा ही दक्षिण एशिया का भारतीय राष्ट्रवाद है। आज न कोई अरब राष्ट्र राज्य' है, न ही यूरोप का एक 'राष्ट्र राज्य' है, अफ्रिका को तो उपनिवेशवाद ने भयानक रूप से बांट दिया है। एशिया व अफ्रिका की सांस्कृतिक राष्ट्रीयताओं को उपनिवेशवाद ने बांटा तथा सेनाएं खड़ी कर दी। उपनिवेशवाद के पूर्व राष्ट्रों की सीमाएं सेना–मुक्त थीं। राष्ट्र राज्य' की कृत्रिम स्थापना ने सेनाओं से घिरी सीमाओं का निरूपण किया है। वर्तमान काल में पहुंची इन स्थितियों को समझते हुए प. पू. श्री गुरुजी (मा. स. गोलवलकर) ने दो प्रकार के राष्ट्रवादों का विवेचन किया है। प्रथम् 'भू–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' (Geo-Cultural Nationalism) तथा द्वितीय राजनैतिक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद' (Politico Territorial Nationalism) 'भू–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' मानवीय है वसुधैव कुटुम्बकम् का सर्जक है, जबकि 'राजनैतिक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद' युद्धकामी तथा साम्राज्यवाद का सर्जक है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानव की स्वाभाविक वैविध्य का सर्जक है। मानवीय एकता का अर्थ इस स्वाभाविक वैविध्य की समाप्ति नहीं हो सकता। दीनदयाल जी के अनुसार "शून्य में मानव एकता का विचार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीयताओं को समाप्त कर इस्लाम व ईसाइयत ने दुनियां को एक करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह अस्वाभाविक था। अतः इनकी असफलता निश्चित थी। इन अप्राकृतिक प्रयत्नों से समाज की हानि हुई, मानवीय एकता की स्थापना व राष्ट्रीयताओं का तिरोहन तो नहीं हो सका, परन्तु इन्होंने राष्ट्रीय जनों में मजहबी दरार उत्पन्न कर दी। इसी प्रकार कम्युनिज्म का अंतर्राष्ट्रीयतावाद भी असफल हुआ। 'राष्ट्रवाद' के आधार पर स्वयं कम्युनिज्म ही बंट गया। 'विश्ववाद' व 'अंतर्राष्ट्रीयता' के सब नारे अंततः 'साम्राज्यवाद' के औजार बने।'

भू. जन एवं संस्कृति के संघात से राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीयता कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, यह स्वाभाविक होती है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को ही भारतीय शास्त्रकारों ने चिति का नाम दिया है। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं जो चिति की अनुकूल हो, उसे संस्कृति तथा जो चिति के प्रतिकूल हो उसे विकृति कहते हैं। यह संस्कृति तत्व ही राष्ट्रीयत्व का नियामक है। मजहब एवं राजनीति के प्रवेश ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अस्मिताओं को आहत किया है।

अखण्ड भारत में आस्थाः

मजहब कहीं भी राष्ट्रीयता का आधार नहीं होता, लेकिन सांस्कृतिक भारत को मजहब के नाम पर बांटा गया। राजनीति भी राष्ट्रीयता की नियामक नहीं होती लेकिन कहा गया कि हम 1947 में नया राष्ट्र बने हैं। परिभाषाहीन राष्ट्रीयता एक मजाक बन गयी। एक व्यक्ति जब जन्मा तो उसकी राष्ट्रीयता भारतीय थी, युवा हुआ तो उसकी राष्ट्रीयता पाकिस्तानी हो गयी तथा प्रौढ़ावस्था में आने पर उसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता बंगलादेशी हो गयी। राष्ट्रवाद की विकृतिपूर्ण अवधारणा का यह दुष्परिणाम है। अतः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पोषक दीनदयाल उपाध्याय अखण्ड भारत के समर्थक हैं। वे अपने ऐतिहासिक 'सिद्धांत और नीतियां प्रलेख में लिखते हैं:

''पाकिस्तान की जनता मूलतः भारतीय राष्ट्र की अंग है। वह पृथकतावादी राजनैतिक शक्तियों का शिकार बनकर अलग हुई है। पाकिस्तान की निर्मिति के बाद से वह बराबर पीड़ित

है। जिस स्वर्ग की उन्हें आशा दिखाई गई थी वह मृग–मरीचिका सिद्ध हुई।"

दीनदयाल उपाध्याय भारत की भ्रमोत्पादक राजनीति से अप्रभावित रहते हुए निरंतर 'अखण्ड भारत' के पक्षधर रहे। 1952 से लेकर 1967 तक प्रत्येक घोषणा–पत्र में अखण्ड भारत का उल्लेख है। 1971 में दुर्भाग्य से उनकी अनुपस्थिति में चुनाव हुआ तथा घोषणा–पत्र में 'अखण्ड भारत' को स्थान नहीं मिला। वे कहते हैं "वास्तव में भारत को अखंड करने का मार्ग युद्ध नहीं है। युद्ध से भौगोलिक एकता हो सकती है, राष्ट्रीय एकता नहीं। अखण्डता भौगोलिक ही नहीं, राष्ट्रीय आदर्श भी है।

देश का विभाजन दो राष्ट्रों के सिद्धांत तथा उसके साथ समझौते की प्रवृत्ति से हुआ। अखण्ड भारत एक राष्ट्र के सिद्धांत पर मन–वचन एवं कर्म से डटे रहने पर सिद्ध होगा। जो मुसलमान आज राष्ट्रीय दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वे भी आपके सहयोगी बन सकेंगे, यदि हम राष्ट्रीयता के साथ समझौते की वृत्ति त्याग दें। आज की परिस्थिति में जो असंभव लगता है वह कालांतर में संभव हो सकता है, किन्तु आवश्यकता है कि आदर्श हमारे सम्मुख सदा ही जीवित रहे।"

दीनदयाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति के लिए हिन्दू संस्कृति शब्द का भी उपयोग करते हैं। "यदि हम एकता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीयता, जो कि हिन्दू राष्ट्रीयता है तथा भारतीय संस्कृति, जो कि हिन्दू–संस्कृति है, उसका दर्शन करें, उसे मानदण्ड मानकर चलें। भागीरथी की इस पुण्यधारा में सभी प्रवाहों का संगम होने दें। यमुना भी मिलेगी और अपनी सभी कालिमा खोकर गंगा की धवल धारा में एकरूप हो जाएगी।'

हिन्दू राष्ट्रीयता है मजहब नहीं तथा मुस्लिम मजहब है राष्ट्रीयता नहीं। अतः उन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए 'मोहम्मद पंथी हिन्दू शब्द का भी प्रयोग किया। भारत के मुसलमान भारत की ओरस संतानें हैं। सांस्कृतिक रूप से वे पृथक नहीं हैं। सभी भारतीय महापुरुष उनके भी पूर्वज हैं।'

क्षेत्रीय सम्प्रभुता के आधार पर 1947 में जो नया राष्ट्र बनाने चले थे, वे समझते थे कि भारत के जिस भू–खण्ड पर अंग्रेजों का राज्य है, वह 'ब्रिटिश इंडिया' ही केवल भारत है। अतः जब नेपाल के कुछ लोगों ने कहा कि जब आप ब्रिटिश इंडिया अनुबंधित सभी रियासतों को भारत में मिला रहे हो, तो नेपाल भी एक रियासत है, उसे भारत में सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे। तब उत्तर दिया गया था हमने अंग्रेजों से उत्तराधिकार में राज्य प्राप्त किया है, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को दो राष्ट्र राज्यों में विभक्त करके हमें सौंपा है, अतः ब्रिटिश इंडिया के बाहर के किसी प्रदेश को यदि हम भारत में मिलाएंगे, तो दुनिया हमें विस्तारवादी कहेगी। यहां तक कि पुर्तगाल से गोवा को मुक्त करवाने के लिए भी राष्ट्रवादी लोगों को आंदोलन करना पड़ा। राजनीतिक राष्ट्रीयता के विकृत भाव ने हमें अखण्ड भारत से साक्षात्कार नहीं करने दिया तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि के अभाव के कारण हमने मजहब आधारित भारत विभाजन स्वीकार कर लिया।

चिति का चैतन्य एवं विराट की शक्ति

चिति द्वारा जो राष्ट्रीयता का साक्षात्कार होता है, पाश्चात्य प्रभावित नेतृत्व ने अपने आपको उसे चिति से काट लिया था। परिणामतः वे मजहबी पृथकतावाद का सामना न कर सके तथा राजनैतिक सम्प्रभुता एवं सांस्कृतिक एकात्मता का समन्वय नहीं कर सके। इसी कारण हमें विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी तथा इसी कारण आज हमें कश्मीर समस्या एवं मजहबी आतंकवाद को झेलना पड़ रहा है।

जब कोई प्रजागृत चिति वाला समाज आत्म–दर्शन करता है तो उसे विराट के दर्शन होते हैं। विराट समाज का शक्ति–भूत तत्व है। 'दैशिक शास्त्र' में लिखा है "चिति से जागृत व एकीभूत हुई समष्टि की प्राकृतिक क्षात्र शक्ति विराट कही जाती है।" भविष्य पुराण के अनुसार यह समाज एक ही पिता प्रजापति ब्रह्मा या विराट ने बनाया है।

''ऋग्वेद में संपूर्ण मानव समाज की एक विराट पुरुष के रूप में कल्पना की गई है जिसके सहस्रों सिर, सहस्रों आँखें, सहस्रों पैर हैं। यह विराट पुरुष संपूर्ण भूमि विस्तार से भी बढ़कर है। जैसे कि एकात्म मानव देह के मुख, बाहु, उदर और पैर, ये चार प्रमुख अवयव हैं, उसी प्रकार मानव समाज रूपी विराट पुरुष के भी समाज में ज्ञान–विज्ञान का विस्तार करने वाले ज्ञानवान पुरुष, दुर्जनों से समाज की रक्षा करने वाले शूरवीर पुरुष, समाज के भरण–पोषण की सामग्री का उत्पादन एवं विपणन करने वाले उद्यमी पुरुष और विभिन्न समाजोपयोगी कामों में लगे लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने वाले सेवापरायण पुरुष ये चार प्रमुख अंग हैं:

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशांगुलम्।।
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू रान्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद्वैष्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।।
(ऋग्वेद 10/90/1,12)

विराट पुरुष के हजार सिर हैं, हजार आँखें हैं, हजार पैर हैं। संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त कर वह पुरुष दशांगुल भाग पर स्थित हो गया। उसका मुख ब्राह्मण हुआ, भुजाएं क्षत्रिय हुई, जंघा वैश्य और पैरों से शूद्र हुआ।)

विराटता का अनुभव समाज को अपनी अपरिमित शक्ति का साक्षात्कार करवाता है। जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पृथक–पृथक जातीय अस्मिताएं नहीं वरन् एक ही विराट पुरुष के अंगभूत हैं। समष्टिगत स्वस्थ संपूर्णता का नाम है विराट। विराट की इस प्राचीन भारतीय अवधारणा को अधुनातन संदर्भ देने का प्रयास करते हुए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, "जैसे राष्ट्र का अवलम्ब चिति होती है, वैसे ही जिस शक्ति से राष्ट्र की धारणा होती है उसे 'विराट' कहते हैं। 'विराट' राष्ट्र की वह कर्मशक्ति है जो 'चिति' से जागृत और संगठित होती है। विराट का राष्ट्र जीवन में वही स्थान है जो शरीर में 'प्राण' का। प्राण से ही इंद्रियों को शक्ति मिलती है, बुद्धि को चैतन्य प्राप्त होता है और आत्मा शरीरस्थ रहती है। राष्ट्र में भी विराट के सबल होने पर ही उसके भिन्न–भिन्न अवयव अर्थात् संस्थाएं सक्षम और समर्थ होती हैं। 'विराट' के आधार पर ही 'प्रजातंत्र' सफल होता है और बलशाली बनता है।

मिश्रित संस्कृति व संघात्मक विकृति है:

चिति और विराट की अवधारणा मिश्रित संस्कृति एवं विघटनवादी अस्मिताओं के विचार का निषेध करती है। न तो चिति को तोड़ा जा सकता है, न विराट को बांटा जा सकता है। समाज की चिति उसकी संस्कृति में व्यक्त होती है तथा एकात्मता विराट में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए दीनदयाल जी संस्कृति व क्षेत्र के नाम पर मजहबी व भाषिक पृथकताओं पर करारी चोट करते हैं। वे वैविध्य को समाज का शृंगार व शक्ति मानते। लेकिन विघटन एवं पृथकता को अवांछनीय विकृति मानते हैं। अतः 1947 में उत्पन्न हुए राष्ट्र राज्य को ही अपना राष्ट्र मानने वाले, भाषा के आधार पर राज्यों को मूल इकाई तथा भारत को संघ मानने वाले तथा मजहब के आधार पर भिन्न–भिन्न संस्कृति को मान्यता देने वाले लोग जो सामान्यतः वामपंथी तथा कुछ कांग्रेसी भी हैं, दीनदयाल जी द्वारा व्याख्यायित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कटुआलोचक हैं।

दीनदयाल उपाध्याय सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता के सबल पुरोधा हैं वहीं विकेन्द्रीकृत अर्थ व राजसत्ता के उग्र समर्थक हैं। सत्ता और वित्त का केन्द्रीकरण उन्हें अभिप्रेत नहीं है। वे समाज व्यवस्था में राज्यसत्ता के न्यूनतम हस्तक्षेप के हिमायती हैं:

''...... समाज की व्यवस्था तथा उसके जीवन का नियमन करने वाली, व्यवस्था देखने वाली, समाज की अनेक संस्थाएं हैं। उनका प्रादेशिक और व्यावसायिक दोनों आधारों पर गठन हुआ है। पंचायतें और जनपद सभाएं हमारे यहां रही हैं। बड़े से बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम राजा ने भी कभी पंचायतों को समाप्त नहीं किया। इसी प्रकार व्यावसायिक संगठन भी रहे, उन्हें भी किसी ने समाप्त नहीं किया, अपितु उनकी स्वायत्तता को सदैव स्वीकार किया गया। अपने–अपने क्षेत्र में उन्होंने नियम बनाए। जाति की पंचायतें, श्रेणियां, पूग, निगम, ग्राम पंचायतें तथा जनपद सभाएं आदि संस्थाएं स्वतंत्र नियम बनाती थीं। राज्य का काम यही था कि इन नियमों का पालन होता है या नहीं, यह देखें। राज्य ने कभी उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार हमारे यहां राज्य तो जीवन के थोड़े से हिस्से को ही छूता था।"

दीनदयाल उपाध्याय एवं उनके भू–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वे ही लोग खिलाफ हैं जिन्हें पाश्चात्योद्भूत 'राष्ट्र राज्य की अवधारणा का ही केवल ज्ञान है। वे न भारत की 'चिति' को समझते हैं, न 'विराट' को। राष्ट्र राज्य ने चितियों एवं विराट को खण्ड–खण्ड कर रखा है। राष्ट्र–राज्य के चंगुल में फसा है भू–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अफ्रिकी राष्ट्रवाद, अरब राष्ट्रवाद एवं यूरोपीय राष्ट्रवाद आज आकार नहीं ले पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद भी इसीलिए कसमसा रहा है। हिन्दुकुश से शृंगपुर तथा त्रिविष्टप (तिब्बत) से सिंहलद्वीप तक फैला भारतीय विराट जब अपनी चिति को प्राजागृत करेगा, तभी भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुखरित होगा।

दक्षेस एवं हिन्द-पाक महासंघ:

दक्षिण एशिया या दक्षेस देशों का संगठन एक अच्छी शुरूआत है। डॉ. लोहिया व दीनदयाल उपाध्याय ने एक साझे वक्तव्य में 'भारत–पाक महासंघ की मांग की थी। अखण्ड भारत या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई राजनैतिक दुराग्रह नहीं है। वस्तुतः यह हमारी चिति का स्वर है। हमें अपने विराट को जागृत करना है। अपने बम्बई के प्रख्यात भाषणों का समापन करते हुए आह्वान किया "हमें अपने राष्ट्र

के विराट को जागृत करने का काम करना है। अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर, वर्तमान यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य के प्रति महत्वाकांक्षा लेकर इस कार्य में जुट जाएं। हम भारत को न तो पुराने समय की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न रूस या अमेरिका की अनुकृति।

भारतीयकरण आवश्यक:

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह चिंतन पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विरासत में प्राप्त किया था। भारतीय जनसंघ के प्रथम कानपुर अधिवेशन में उन्होंने 'सांस्कृतिक पुनरूत्थान' शीर्षक से एक बीजभूत प्रस्ताव रखा। भौगोलिक किंवा क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की कल्पना को नकारते हुए उन्होंने कहा– "हिन्दू समाज का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि भारतीय जनजीवन के तथा अपने उन अंगों के भारतीयकरण का महान कार्य अपने हाथ में ले जो विदेशियों द्वारा स्वदेशपराङ्मुख तथा प्रेरणा के लिए विदेशाभिमुख बना दिये गए हैं। हिन्दू समाज को चाहिए कि उन्हें स्नेहपूर्वक आत्मसात् कर लें। केवल इसी प्रकार साम्प्रदायिकता का अंत हो सकता है और राष्ट्र का एकीकरण तथा दृढ़ता निष्पन्न हो सकती है।

भारतीयता राष्ट्रीयता को सुपरिभाषित करने में सबसे बड़ी कठिनाई, भारत की आजादी के आंदोलन में जिस द्वि–राष्ट्रवाद का हस्तक्षेप हुआ तथा भारत का विभाजन हुआ। खण्डित भारत में भी उसी प्रवृत्ति का पोषण होकर मिश्रित संस्कृति के एक अजनबी तथ्य का इस बहस में प्रवेश करवा दिया गया है। दुनियां का कोई भी राष्ट्र अपने देश की संस्कृति को मिश्रित संस्कृति नहीं कहता है। भारत एक जन एवं एक संस्कृति है, यहां एक सांस्कृतिक राष्ट्र चिरकाल से विद्यमान है। भारतीय संस्कृति मजहबों व उपासना पद्धतियों की बहुलता को न केवल स्वीकार करती है वरन् इस प्रवृत्ति को सम्मान देते हुए उसे संरक्षित रखने की व्यवस्था भी करती है। इस संस्कृति का आधार ही है 'एकम् सत् विप्र बहुधा वदंति।' आज दिखाई दे रहे टूटे–फूटे तथा टूटते–फूटते भारत की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है, 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' को समझ कर उसे अपने जीवन में अपनाया जाए। तो हम विश्वभर की कसमसाती राष्ट्रीयताओं के लिए एक आशा का दीप बनेंगे। उपनिवेशवादी सीमाओं से निजात पाकर विश्व–मानव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का साक्षात्कार कर सकेगा। यात्रा लम्बी है, लेकिन यही लघुतम मार्ग है। इस पर चलना होगा। ❑❑❑

Team LUB joined India-UK Business Delegation Recently, the members of Laghu Udyog Bharati represented the organisation at the India-UK Business Delegation under the leadership of Shri Piyush Goyal, Union Minister of Commerce & Industry, Govt. of India, strengthening India-UK business and industry relations and advancing the interests of India's MSME sector in London. CA Aditya Mitruka Siliguri, North Bengal participated in an Interaction Session. Other key persons attending the meet were Shri Neeraj Sehgal-Delhi, Shri Jayesh Dedhia-Mumbai, Shri Nilesh Patel, Shri Upendra Patel, Shri Satish Savani and Shri Chandresh Sankharva-Gujarat & Shri Pawan Singhal from Uttar Pradesh.

LUB's National Co-Treasurer CA Nirmal Kumar Ojha, presented PPT with suggestions regarding the Companies (Amendment) Bill, 2026, before the Joint Parliamentary Committee constituted for the Bill on 10th July. The Committee accepted most of Laghu Udyog Bharati's suggestions and incorporated them into its report. Shri Ojha is seen with Chairman JPC & MP-Mandsaur Shri Sudhir Gupta.

LUB's Arunachal Pradesh state unit successfully organized its sensitization General Meeting at Itanagar on July 16. The meeting was graced by Shri Nima Sona- President, Shri Nyanya Gollo- General Secretary, Smti Tage Rita-Treasurer, Shri Henium Takung-Convenor along with all EC members and many enthusiastic upcoming entrepreneurs.

Strengthening the Spine of Atmanirbhar Bharat:
A Strategic Review of MSME Development (Amendment) Bill, 2026

Analysis
CA Nirmal Kumar Ojha
National Joint-Treasurer
Laghu Udyog Bharati
canirmalkumarojha@gmail.com

The micro, small, and medium enterprise (MSME) sector serves as a primary engine of India's economic growth, contributing significantly to domestic manufacturing, regional employment, and export potential. Within this vibrant ecosystem, micro and small enterprises (MSEs) form the actual bedrock of grassroots industrialization and decentralized economic development.

To align the regulatory framework with modern technological advancements and changing market dynamics, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises introduced the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026 in the Rajya Sabha on 28th July, 2026. The legislation proposes essential amendments to the MSME Development Act, 2006 to enhance the sector's global competitiveness, improve regulatory efficiency, and deepen ease of doing business across states.

Laghu Udyog Bharati (LUB) welcomes this landmark legislative update. The 2026 Bill directly addresses key priorities for small enterprises: unlocking working capital through mandatory TReDS mechanisms, enforcing structured timeframes for dispute resolution, providing cash-flow relief during judicial challenges, and transitioning toward a facilitative, civil penalty framework.

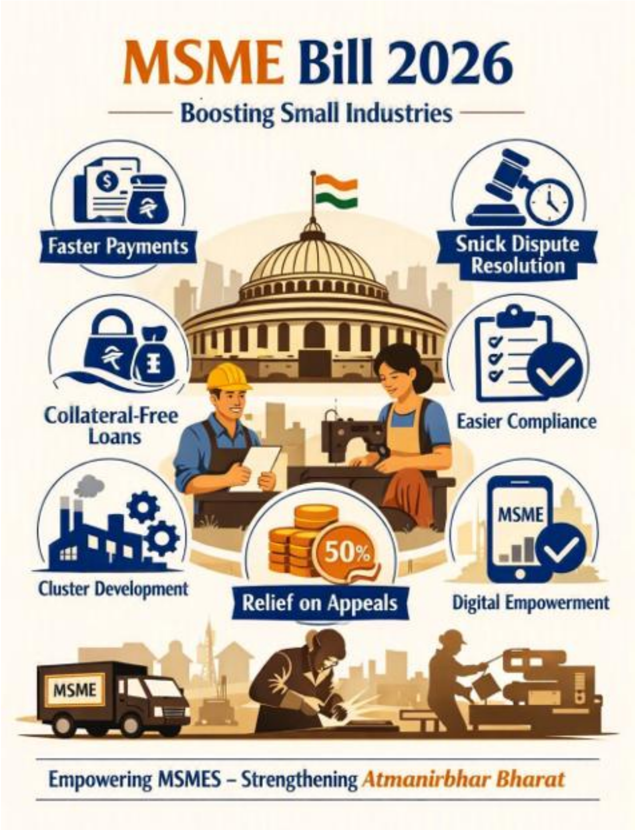

1. Encouraging Modernization: Safeguarding Investments in R&D and Safety Statutory Mechanism (Section 7)

Under Section 4 of the Bill, which amends Section 7 of the principal Act, the Central Government retains the flexibility to notify MSME classification limits based on investment in plant, machinery, or equipment and annual turnover.

Statutory Provision- Explanation 1 of Section 7:

"In calculating the investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development, industrial safety devices and such other items as may be specified, by notification, shall be excluded."

Strategic Perspective

To remain competitive, small units must adopt green technologies, implement safety protocols, and invest in

innovation. Previously, capital spent on safety or R&D counted toward investment ceilings, creating an inadvertent risk of losing MSME status. Excluding pollution control, safety devices, and R&D expenses ensures that enterprises can upgrade their facilities and meet environmental standards without losing their MSME registration and associated benefits.

2. Resolving Liquidity Bottlenecks: Mandatory Invoice Settlement via TReDS Statutory Mechanism (Section 15A & Section 22A)

Persistent payment delays remain a significant operational challenge for micro and small units. To address liquidity constraints, Section 15A establishes a mandatory electronic discounting framework:

- **Mandatory CPSE Routing:** Every Central Public Sector Enterprise (CPSE) must route the settlement of invoices for procurements from MSMEs through an RBI-authorized Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform.
- **State and Public Entity Inclusion:** Central and State Governments are empowered to extend this mandatory TReDS framework to State PSUs, local bodies, and autonomous authorities.
- **Compliance Transparency (Section 22A):** Obligates specified public sector entities to formally disclose details of invoices routed and settled through TReDS platforms, fostering accountability.

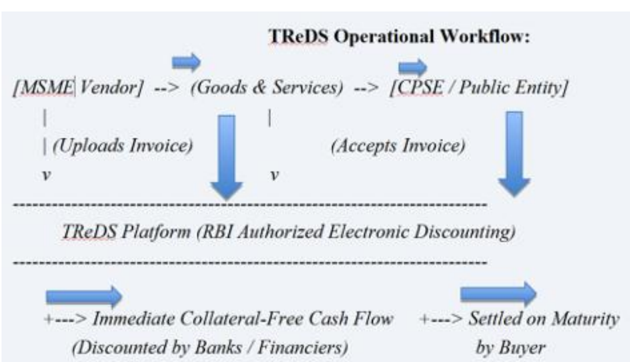

Strategic Perspective

TReDS shifts the financing reliance away from the small supplier onto institutional platform financiers. Once an invoice is accepted by a CPSE, competitive bidding allows vendors to receive immediate liquidity at favorable rates based on the buyer's credit standing.

Laghu Udyog Bharati encourages State Governments to notify their respective State PSUs and local bodies under Section 15A(3) upon enactment. Extending TReDS to state-level entities will ensure consistent payment flows across regional industrial corridors.

3. Streamlining Dispute Resolution: Binding Timelines & Online Dispute Mechanisms Statutory Mechanism (Section 18 & Section 18A)

To improve delayed payment recovery mechanisms under the Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC), Sections 18 and 18A introduce structured procedures and expanded jurisdiction:

- **Mediation Window:** Mediation must be completed within 90 days from the first appearance date.
- **Arbitration Initiation:** If mediation is unsuccessful, arbitration must commence within 30 days of termination.
- **Arbitral Awards:** Final arbitral awards must be delivered within 90 days from the completion of pleadings.
- **Expanded Territorial Jurisdiction:** Councils can entertain claims where the supplier is registered within their local jurisdiction, irrespective of where the buyer is located across India.
- **Online Dispute Resolution (ODR) (Section 18(6)):** Empowers the Central Government to establish a digital framework for mediation and arbitration using video conferencing, electronic filings, and digital evidence recording.
- **Enforcement Measures (Section 18A):** Mediated settlements and arbitral awards are recoverable as arrears of land revenue through the District Collector and are recognized as valid debts under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016.

Strategic Perspective

Establishing clear procedural windows and expanding jurisdiction simplifies access to redressal for small businesses. Furthermore, digital ODR capabilities reduce travel costs and administrative delays, while land revenue recovery status provides strong legal enforceability for Council awards.

4. Cash-Flow Safeguards in Appeals: The 50% Release Provision Statutory Mechanism (Section 19)

Under the substituted Section 19, non-supplier applicants challenging an award in court must still deposit 75% of the awarded amount. However, to protect small vendors during extended court proceedings, the Bill introduces a crucial proviso:

Statutory Safeguard - Proviso to Section 19(2):

"Provided that if the application has been pending for more than six months, the court shall order to pay to the supplier a sum equivalent to at least fifty per cent. of the amount awarded from the amount deposited by the applicant."

Strategic Perspective

By ensuring that at least half of the deposited funds are released to the vendor if a judicial challenge exceeds six months, this safeguard maintains liquidity during lengthy litigation. It aligns legal remedies with operational requirements, ensuring small enterprises retain necessary cash flow.

5. Modernizing Governance: Decriminalization & Civil Penalties Statutory Mechanism (Section 27 & Section 27A)

The Bill shifts from conviction-based penalties toward a graded civil penalty framework, promoting a compliance-driven regulatory environment:

Parameter	Previous Framework (2006 Act)	Proposed 2026 Framework
Section 8/26 Non-Compliance (Registration/filing details)	Criminal conviction; fines up to ₹1,000 (1st instance) and ₹10,000 (subsequent)	First Instance: Statutory Warning Subsequent Instances: Civil penalty from ₹1,000 to ₹50,000
Section 22 Non-Compliance (Buyer disclosures)	Fine not less than ₹10,000	First Instance: Statutory Warning 2nd Instance: ₹10,000 to ₹50,000 3rd + Instance: ₹50,000 to ₹1,00,000
Adjudication Framework	Criminal Court proceedings	Adjudicating Officer: Development Commissioner Appellate Mechanism: Secretary, Ministry of MSME (30-day filing window; 60-day target disposal)
Periodic Adjustments	Fixed statutory amounts	Minimum penalty rates can be enhanced by up to 10% every 3 years via notification

Strategic Perspective

Replacing criminal sanctions with warnings for initial technical omissions and establishing administrative adjudication under the Development Commissioner reduces legal friction for enterprise owners. The structured 60-day appellate timeframe provides procedural certainty, encouraging voluntary compliance while maintaining proportionate enforcement.

6. Strengthening Institutional Capacity

- **National Digital Platform (Section 8):** Authorizes a simplified, voluntary National Digital Platform for electronic registration and central benefit access, designed to work seamlessly alongside State platforms.
- **Expanding Council Capacity (Section 20 & 21):** Authorizes State Governments to establish additional MSEFCs to clear case backlogs, equipping them with required digital infrastructure, regular meeting schedules, and 3-to-5-member panels that include mandatory representation from industry associations and legal experts.

Strategic Recommendations for Implementation

To maximize the practical benefits of the 2026 Amendment Bill, Laghu Udyog Bharati highlights the following administrative steps:

- **State-Level Adoption of TReDS Mandates:** State Governments should issue prompt notifications under Section 15A(3) to extend mandatory TReDS invoice routing to State PSUs, municipal bodies, and state procurement departments.
- **Unified Digital Integration:** The National Digital Platform under Section 8 should be integrated with TReDS and ODR portals to streamline enterprise registration and dispute filing.

- **Establishing Regional MSEFC Benches:** States with high industrial concentration should exercise powers under Section 20 to set up additional regional MSEFCs, ensuring disputes are resolved within the 90-day target.
- **Stakeholder Awareness Programs:** The Ministry of MSME and industry bodies like Laghu Udyog Bharati can collaborate on regional workshops to educate micro and small entrepreneurs on utilizing ODR tools, accessing TReDS liquidity, and understanding the civil compliance framework.

Framework for Strengthening Future Provisions

Future MSME amendments should embed statutory reforms in credit access, cluster infrastructure, insurance, and sustainability within the MSMED Act for enforceability. Dynamic areas such as digital adoption, skill development, and export promotion can remain flexible through schemes. This dual approach ensures legal certainty for core needs while allowing agile policy updates, creating a balanced framework that strengthens MSMEs as the backbone of Atmanirbhar Bharat.

In addition, execution of MSEFC decrees must be reinforced by introducing dedicated Execution Officers at district, tehsil, and industrial-area levels. These officers would ensure that Council awards are enforced promptly, delivering relief directly to grassroots enterprises and minimizing systemic delays in recovery.

The TReDS execution and recovery mechanism should also be strengthened by shifting recovery responsibilities toward the platform itself. Empowering TReDS platforms to initiate recovery proceedings against defaulting buyers would create a faster, technology-driven enforcement channel, reducing dependence on prolonged administrative or judicial processes.

Furthermore, penalties for defaulting buyers should be enhanced beyond mere decriminalization. Stronger deterrents-such as higher graded fines, suspension from procurement eligibility, or blacklisting from government tenders-would ensure that the true objective of the Act is achieved: freeing up blocked capital and safeguarding MSME liquidity. Without meaningful consequences, buyers may continue delaying payments, undermining the spirit of the legislation.

By incorporating these measures, the MSME framework will evolve from being reactive and compliance-driven to proactive and growth-oriented, ensuring that reforms translate into tangible benefits for enterprises across Bharat.

❑❑❑

LUB's Belagavi Unit and KLS Gogte Institute of Technology (KLS GIT), Belagavi have signed a MoU to foster stronger industry-academia collaboration on 17th July. The MoU was signed by Shri Mahesh Inamdar, President-Belagavi Unit, and Shri Rajendra Belgaumkar, Chairman, KLS GIT, in the esteemed presence of Shri Prakash Chandra Ji-National Organizing Secretary and Dr. Sachin Sabnis-National Vice President-LUB, Dr. Vijay Athavale-Principal, KLS GIT, and faculty members of the Mechanical Engineering Department. This collaboration reflects a shared commitment to nurturing industry-ready talent, driving innovation, supporting MSMEs, and contributing towards the vision of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047.

My Entrepreneurial Journey, My Faith and My Dream for BHARAT

Udyam Yatra

Sushil Kumar Bahety
Leading Entrepreneur
Member, Laghu Udyog Bharati,
West Bengal
skbahety@smitabh.com

India is passing through one of the most exciting periods in its history. Under the visionary leadership of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, the country has set a clear goal of becoming Viksit Bharat by 2047. I believe this is not only the vision of the Government; it is the responsibility of every Indian who wants to see our nation prosperous, self-reliant and respected across the world.

I was born into a well-established Marwari business family with a long tradition of trade and exports. After completing my Higher Secondary education, I joined the family business in 1969. Those early years were my real education in business. I learnt accounts, office work, discipline and, above all, the importance of relationships and trust in business.

Hot-Dip Galvanising Unit

Over the years, my journey took me through several manufacturing sectors-footwear, food processing, plastic packaging, cotton and canvas bags and Reverse-Printed BOPP woven sacks for branded Agri-packaging. One of the most memorable chapters was our export-oriented HDPE bag business, manufacturing shopping/carrier bags and garbage bags. The business grew into a significant exporter and was honoured with the **Largest Exporter Award by PLEXCONCIL** in this category. I will always cherish this recognition because it represented the collective effort of our entire team.

My industrial journey took a new direction when we established our steel fabrication business in 2011 and subsequently our hot-dip galvanising unit in 2018.

In 2012, we took over a sick potato wafer and namkeen manufacturing unit. At a time when many would have considered a closed factory a liability, I saw an opportunity-to revive an existing industrial asset, restore production and, most importantly, restore employment.

The revival was not easy. It required teamwork, discipline, quality improvement and continuous attention to productivity. Gradually, the unit became a successful and sustainable manufacturing business.

Today, the businesses under my direct association have reached an annual turnover of approximately **₹400 crore in 2025-26**, and we have set ourselves a target of approximately **20% annual growth**. Our businesses directly employ more than **1,400 people**, supporting the livelihoods of more than **1,400 families**.

Steel Fabrication Unit

For me, these numbers are important, but they are not the real measure of success. The real satisfaction comes from knowing that our factories provide livelihoods, develop skills and give people the opportunity to build better lives for their families.

Our family also has several other manufacturing and trading businesses, which are being managed by the younger generation. This gives me confidence that the entrepreneurial spirit and values of our family will continue into the future.

From the India I Knew to the India I See Today

At 76, I feel privileged to have witnessed India change over several decades. When I began my business journey, finance was difficult to arrange, technology was not easily available, infrastructure was limited and doing business involved many challenges.

Today, the picture is very different.

India has better highways, railways, ports and airports. Digital technology has transformed the way businesses operate. Technology and automation are becoming increasingly accessible. Indian entrepreneurs are more confident, and Indian manufacturing is earning greater respect around the world. This transformation gives me tremendous optimism.

I sincerely congratulate our Hon'ble Prime Minister, **Shri Narendra Bhai Modi Ji**, for his vision of **Viksit Bharat-2047**. I believe the direction in which India is moving today, supported by improvements in infrastructure, technology, digitalisation, manufacturing and entrepreneurship, is creating the foundation for a stronger and more self-reliant India. However, I also believe that Viksit Bharat is not only the responsibility of the Government. It is our responsibility too.

Every entrepreneur must create employment.

Every industry must improve productivity.

Every manufacturer must focus on quality.

Every worker must take pride in his work.

Every business must operate with honesty and transparency.

India cannot become a developed nation merely because we have lower costs. We must become globally competitive because our **quality is better, our technology is stronger, our delivery is reliable and our commitment is unquestionable**.

For MSMEs, modernization, automation, digital manufacturing, artificial intelligence and skilled manpower are becoming essential for future growth.

My Dream for West Bengal

Being an industrialist from West Bengal, I have a special dream for this state. West Bengal has everything

required to become a major industrial centre-talented people, hardworking workers, a strategic location, ports and a long industrial heritage. What we need is a strong and sustained industry-friendly environment.

I look forward to faster approvals, better infrastructure, easier availability of industrial land, improved connectivity and greater encouragement for entrepreneurs and MSMEs.

If these conditions continue to improve, I believe West Bengal can once again emerge as one of India's leading industrial states. A strong West Bengal will mean more factories, more investment, more employment and a greater contribution to the national vision of **Viksit Bharat @ 2047**.

What I Tell Young Entrepreneurs

Young entrepreneurs sometimes ask me about the secret of success. My answer is very simple:

Work hard.

Be honest.

Respect your workers.

Never compromise on quality.

Keep learning.

Never lose courage during difficult times.

There is no shortcut to sustainable success. It comes through patience, discipline and continuous improvement.

Even today, I enjoy visiting my factories and discussing production, quality, productivity, technology and future expansion with my team. I believe that **age should never become a barrier to learning**.

Whatever I have achieved has not been mine alone. It has been made possible by the blessings of God, the support of my family, the dedication of my employees, the trust of our customers and the guidance of many well-wishers. I remain grateful to all of them.

I have complete faith that India will become a developed nation by 2047. Our youth have talent. Our entrepreneurs have courage. Our workers have dedication. If we all work together with honesty, discipline, innovation and commitment, I believe no goal is beyond our reach.

I would like to end with a thought that has guided me throughout my industrial journey:

Factories do not merely manufacture products. They create employment, build confidence, support families and strengthen society. Every honest entrepreneur is, in my view, a nation builder.

Let us all contribute in our own way and make the dream of **Viksit Bharat-2047** a proud reality for every Indian.

❑❑❑

** Based on the conversation with LUB's National VP & In-charge, West Bengal Shri Saroj Kumar Sahoo @ Kolkata.*

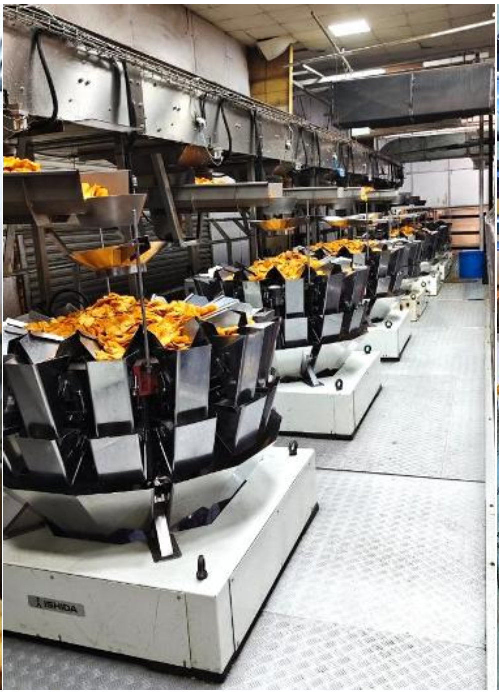

पाली के स्वरोजगार प्रकल्प में आधुनिक मशीनें स्थापित

300 महिलाओं को घर पर ही मिल सकेगा रोजगार

लघु उद्योग भारती की ओर से राजस्थान के औद्योगिक कस्बे पाली में कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार के लिए विविध प्रकल्प संचालित किये जा रहे हैं। हाल ही में पाली में तैयार किये जा रहे सलवार सूट और साड़ी आदि की पैकिंग में काम आने वाले प्लास्टिक पाउच के रोल और साइड की पाइपिंग की कटिंग करने वाली 12 लाख रुपये लागत की अति आधुनिक स्वचालित मशीन 20 जुलाई को स्थापित की गई।

हालांकि मशीन के संचालन में केवल एक कर्मचारी की ही आवश्यकता रहती है, लेकिन इस मशीन से करीब तीन सौ से अधिक महिलाओं को उन्हें घर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि ये मशीन पूर्णतः कम्प्युटराइज़्ड है और एक बार कम्प्यूटर से पाउच की साइज निर्धारित (Fix) करने के बाद उसमें लगा प्लास्टिक रोल आठ घंटों में एक लाख से भी ज्यादा पाउच की कटिंग कर देती है।

लघु उद्योग भारती द्वारा चलाये जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख सूत्रधार और **पाली के पूर्व विधायक श्री ज्ञानचंद पारख** ने बताया कि औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने इन मशीनों को शुभ स्वस्तिक चिन्ह अंकित कर प्रारंभ किया जिनके प्रेरक मार्गदर्शन से पाली में रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने हेतु निरंतर अध्ययन एवं प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले में ये जानकारी मिली थी कि पाली में सलवार सूट, साड़ी एवं अन्य ड्रेस मेटेरियल की पैकिंग के लिए प्रतिदिन लाखों प्लास्टिक पाउच की मांग रहती है। बरसों से पाली के उद्यमी ये पाउच सूरत, मुंबई, कानपुर आदि शहरों से मंगाते रहे हैं। प्लास्टिक के इन पाउच की बड़ी मांग एवं खपत को देखते हुए इन्हें यहीं स्थानीय स्तर पर तैयार करना निश्चित किया।

उल्लेखनीय है कि ये दोनों मशीनें विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स को पूर्व विधायक श्री पारख के आग्रह पर पाली के प्रमुख समाजसेवी

और मेड़तिया स्वीट्स के प्रोप्राइटर श्री राजू भाई मेड़तिया के आर्थिक सहयोग से उपलब्ध करवाई गई है। इस पाउच की सिलाई करने वाली महिलाएं प्रतिदिन करीब आठ सौ से एक हजार रुपये कमा सकेंगी।

श्री पारख ने बताया कि लघु उद्योग भारती के इस प्रयास को देशभर में पाली मॉडल के नाम से ख्याति मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने भी पाली के इस रोजगार मॉडल की सराहना की एवं अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही प्रयास करने का आह्वान किया।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश संयुक्त महासचिव श्री विनय बंब ने जानकारी दी कि संगठन की पहल पर जन सेवा को समर्पित जनप्रतिनिधि श्री पारख ने 19000 से 1.25 लाख रुपए तक की 8700 अत्याधुनिक सिलाई मशीनें महिलाओं को कम कीमत और आसान किस्तों में स्वरोजगार के लिए उपलब्ध करवाई। इसी तरह चूड़ी पर नगीने लगाने की 850 मशीनें एवं मिटटी के कुल्लड़ बनाने की 30 से भी अधिक मशीनें प्रदान की जा चुकी हैं जिससे 15000 से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। स्थानीय सेवा समिति वृद्धाश्रम के माध्यम से भी पिछले 5 वर्षों में दो हजार से अधिक युवतियों को सिलाई मशीन के कार्य के साथ सौंदर्य सज्जा और मेहंदी प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे उनके जीवन में स्वावलंबन परिलक्षित होता है। इस अवसर पर प्रवासी समाजसेवी श्रीमती भगवती बल्दवा ने कहा कि लघु उद्योग भारती के रोजगारपरक प्रयास सराहनीय हैं और इससे पलायन रुकेगा। ❑❑❑

प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी–सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण

राजस्थान में विकास के नए अध्याय की शुरुआत

राज–काज

डॉ. संजय मिश्रा

वरिष्ठ पत्रकार एवं को–एडिटर, उद्योग टाइम्स

dr.sanjay.jpr@gmail.com

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान को 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। अवसर था प्रदेश के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी–सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के 4 जुलाई को विधिवत लोकार्पण का। इस अवसर पर उन्होंने जयपुर मेट्रो परियोजना फेज–2 की नींव रखने के साथ चूरू–सादुलपुर तथा चूरू–रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही लगभग 54 हजार युवाओं को अभिनंदन–पत्र प्रदान किये और 1,300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री के. के. विश्नोई सहित अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

पश्चिमी राजस्थान में विकास का नया सूर्योदय

पचपदरा रिफाइनरी परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। ₹79,459 करोड़ के निवेश से निर्मित इस परियोजना की रिफाइनिंग क्षमता 9 MMTPA तथा पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 MMTPA है। पचपदरा रिफाइनरी अत्याधुनिक तकनीक से विकसित की गई है, जो राजस्थान के क्रूड और आयातित क्रूड के मिश्रण को प्रोसेस करने में सक्षम है। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 और पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26 प्रतिशत से अधिक है, जो इसे दक्षता और संधारणीयता के लिहाज से वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, यह पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क तथा उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम और सहायक उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत उद्योग के रूप में काम करेगी।

जयपुर को 41 किमी. मेट्रो कॉरिडोर की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर मेट्रो फेज–2 की आधारशिला रखी। इसके तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे। परियोजना की

अनुमानित लागत ₹13,037 करोड़ से अधिक है और इसका क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र और राजस्थान सरकार की 50:50 साझेदारी वाली कंपनी है। यह कॉरिडोर सीतापुरा और वीकेआईए औद्योगिक क्षेत्र के साथ जयपुर एयरपोर्ट को भी जोड़ेगा। परियोजना के पहले पैकेज के लिए ₹918.04 करोड़ से अधिक के कार्यों का स्वीकृति पत्र भी जारी किया जा चुका है।

नव चयनित युवाओं को मिले अभिनंदन-पत्र

कार्यक्रम में राजस्थान के लगभग 54 हजार नवचयनित युवाओं को अभिनंदन–पत्र प्रदान किए गए। इनमें प्रशासन, शिक्षा, ऊर्जा, गृह, पंचायती राज, परिवहन, उच्च शिक्षा, कौशल एवं रोजगार, आयोजना, कृषि तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सहित विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं।

उत्तर–पश्चिम राजस्थान में बेहतर हुआ रेल संपर्क प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग ₹892 करोड़ की लागत से तैयार चूरू–सादुलपुर (58 किमी) और चूरू–रतनगढ़ (46 किमी) रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से चूरू सहित उत्तर–पश्चिम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। रेल लाइन की क्षमता बढ़ने से यात्री और मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं समयबद्ध होगा।

प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी ऊर्जा परियोजनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में 1,300 मेगावाट की दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया– एसजेवीएन की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना और एनएचपीसी की 300 मेगावाट करणीसर सौर परियोजना। इन पर क्रमशः ₹5,492 करोड़ और ₹1,677 करोड़ खर्च हुए। परियोजनाओं में स्वदेशी सोलर मॉड्यूल और सेल का उपयोग किया गया है, जिससे मेक इन इंडिया, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा तथा कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने ₹1,910 करोड़ की राजस्थान आरईजेड फेज–3 भाग–एच ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन और फेज–4 भाग–एफ की 530 सर्किट किमी लंबी प्रसारण प्रणाली का शिलान्यास भी किया। इस परियोजना पर ₹2,735 करोड़ खर्च होंगे और इसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नई प्रसारण व्यवस्था से राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी बेहतर होगी और प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

जोधपुर रिंग रोड के फोर लेन का लोकार्पण

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लगभग ₹737 करोड़ की लागत से तैयार एनएच–125ए जोधपुर रिंग रोड सेक्शन–2 (करवड़–डांगियावास) के 30 किमी. से अधिक लंबे फोर–लेन मार्ग का लोकार्पण भी किया। इससे जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर, यातायात अधिक सुगम और सड़क परिवहन सुरक्षित होगा। इस अवसर पर यमुना जल परियोजना से संबंधित समझौते पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए एमओए से दोनों राज्यों की करीब तीन दशक पुरानी जल समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लगभग ₹34,102 करोड़ की परियोजना से राजस्थान की जल सुरक्षा मजबूत होगी। परियोजना के तहत हथिनीकुंड बैराज से 295.5 किमी। लंबी भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से चूरू, सीकर, झुंझुनूं सहित अन्य क्षेत्रों में दीर्घकालिक पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की भंडारण परियोजनाओं के पूरा होने से सिंचाई और अन्य जल आवश्यकताओं को भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी।

❑❑❑

MSME Sector to Play a Major Role in Making India Self-Reliant in Pharmaceutical Manufacturing

'Brand India' to Build a Global Image - JP Nadda

Productive Dialogue Between Government and Entrepreneurs at Historical LUB Pharma Conclave-2026

New Aspirations

Dr. Rajesh Gupta
National Head, LUB Pharma Committee
lub.pharma@gmail.com
dr.rajesh@dallaspharma.com

Union Health Minister Shri JP Nadda inaugurated the Pharma Conclave-2026, organized by the Pharma Product Group of Laghu Udyog Bharati, at the India Habitat Centre in New Delhi on 25th July. On this occasion, LUB's National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra ji, National President Shri Madhusudan Dadu, Former National President & National Coordinator-Product Group Shri Ghanshyam Ojha, National General Secretary Shri Om Prakash Gupta, National Jt. General Secretary Shri Naresh Pareek; Secretary Smt. Anju Bajaj as well as Secretary of the Department of Pharmaceuticals Shri Manoj Joshi, Drug Controller General of India Shri Rajeev Singh Raghuvanshi, entrepreneurs, experts, Drug controllers from ten states, 400 pharmaaceutical manufacturers from across the country were present.

Union Health Minister Shri JP Nadda stated that rapid progress is being made towards making India self-reliant in the pharmaceutical manufacturing sector. He emphasized that the MSME sector would play a crucial role in accelerating India's manufacturing capabilities regarding affordable medicines, bulk drugs, vaccines, and medical devices in the coming years.

He was addressing the inaugural session of the LUB Pharma Conclave-2026, organized by Laghu Udyog Bharati- a national organization dedicated to micro and small industries. The theme of the conclave was 'Roadmap for the Pharma Sector for Viksit Bharat-2047'. He noted that medicines manufactured in India are trusted across the globe today.

The Union Health Minister Shri Nadda urged pharmaceutical entrepreneurs nationwide to focus more on quality products rather than just quantity, thereby enhancing the global image of 'Brand India' under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. He highlighted that India contributes 60 percent of the world's vaccine production and holds a significant share in the $30 billion export market. Shri Nadda commended the work of Laghu Udyog Bharati, noting the organization's success in conveying the challenges faced by small-scale entrepreneurs to the government and ensuring their effective resolution.

This conclave was also historic in that it facilitated a meaningful dialogue between the government and entrepreneurs; an open session was also held during the event, where drug controllers from across the country addressed the entrepreneurs' queries. While briefing pharmaceutical manufacturers on new regulations, **Drug Controller General of India Shri Rajeev Singh Raghuvanshi** stated that they could ensure compliance through MSME clusters. Shri Tukaram Mundhe, Commissioner of the Food and Drug Administration (Maharashtra), highlighted the importance of administrative audits.

Speaking on the occasion, **Shri Manoj Joshi, Secretary of the Department of Pharmaceuticals**, pointed out that whenever MSMEs falter on quality, large companies reap the direct benefit. He emphasized that entrepreneurs in the pharmaceutical industry must strictly adhere to regulations and address existing shortcomings on both regulatory and compliance fronts.

Earlier, **Shri Omprakash Gupta, National General Secretary of Laghu Udyog Bharati**, highlighted the organization's achievements. He noted that the organization has focus on technology transfer with CSIR, skill development, industry-academia collaboration, and onboarding small-scale industries onto the Government of India's GeM portal.

Dr. Rajesh Gupta, Pharma Conclave Coordinator & LUB Pharma Committee Member Shri Sanjay Singla submitted a memorandum detailing the challenges facing the pharmaceutical industry to Health Minister Shri Nadda. National Head-LUB

Pharma Product Group, Dr. Rajesh Gupta urged pharmaceutical manufacturers not to compromise on quality in order to emerge as the L-1 (lowest) bidder.

'Pharma Icon Awards' presented to Entrepreneurs

Five successful entrepreneurs who achieved success by scaling up from the MSME sector to large corporate entities were recognized. On behalf of Shri Ajit Singh-Managing Director, ACG Group Pvt. Ltd. Shri Ravleen Singh Khurana received the Award.

Shri P.K. Datta
(Managing Director, Systopic Laboratories Pvt. Ltd.)

Shri Bodh Raj Sikri
(Managing Director, Next Wave India and ABS Mercantile Pvt. Ltd.)

Shri Ramkumar Jain
(Managing Director, East African India Overseas)

Shri M. Vijay Kiran
(Director, Covalent Laboratories Pvt. Ltd.)

Emerging Pharma Company Award

Shri Ravleen Khurana
MD, Nitika Pharmaceutical Pvt. Ltd. Nagpur

Shri Manish Agrawal
MD, 9M pharmaceutical Ltd. Chhattisgarh

LUB's National President Shri Madhusudan Dadu and Member, LUB Pharma Committee Shri Ravleen Singh Khurana honored Shri Manoj Joshi, Secretary-Department of Pharmaceuticals, GoI by draping a shawl.

LUB's National General Secretary Shri Om Prakash Gupta & National Head, Pharma Committee Dr. Rajesh Gupta presented a memento to Shri Mohit Yadav-IFS, Joint Secretary, Department of Commerce, GoI.

Shri Amit Chawla, Member- LUB Pharma Committee welcomed Shri Manoj Joshi, Secretary-Department of Pharmaceuticals, GoI with a flower bouquet.

Shri Rohit Bhatia, Member- LUB Pharma Committee presented a memento to Shri Shri Rajeev Singh Raghuvanshi- Drug Controller General of India.

Dr. Rajesh Gupta, National Head-LUB Pharma Committee presented a memento to Union Minister Shri J.P. Nadda

Team spirit to make India a leader in the pharmaceutical industry - Union Minister Shri Nadda with the LUB's National Core Team and Pharma Team.

Industry-Academia Connect: July 2026

The month of July marked another significant milestone in Laghu Udyog Bharati's continued efforts to strengthen industry-academia collaboration, promote technology transfer, and develop industry-oriented skill development initiatives for the benefit of MSMEs across the country.

A major focus during the month was LUB's continued engagement with the **National Institute of Open Schooling (NIOS)** in developing industry-aligned vocational education. LUB participated in two stakeholder consultations at the NIOS Headquarters, Noida, to contribute to the development and review of skill-based curricula. On 1st July 2026, Smt. Aarti Sehgal, Shri Neeraj Sehgal, and Shri Raman Chawla represented LUB in the review of the **Fire Marshal Course**, where they shared valuable industry inputs to enhance the practical relevance of the curriculum. Drawing upon his extensive experience in fire safety, Shri Neeraj Sehgal provided key technical recommendations to strengthen the course with greater emphasis on practical training and industry requirements.

Later, on 27th July 2026, Smt. Anju Bajaj, Shri Raman Chawla, and Dr. Arshpreet Kaur represented LUB in another stakeholder consultation for the **Junior**

Technician - Electrical and Electronic Sub-System (NSQF Level-3) course. During the deliberations, LUB emphasized competency-based learning, mandatory On-the-Job Training (OJT), and stronger industry integration to ensure that the curriculum remains aligned with the evolving needs of the manufacturing sector and enhances students' employability. These consultations reaffirm LUB's commitment to supporting the development of industry-driven vocational education that prepares a skilled workforce for India's growing industrial ecosystem.

Continuing its commitment to bridging the gap between research institutions and industry, Laghu Udyog Bharati, in collaboration with the **DST-Technology Enabling Centre (TEC), Punjab University, Chandigarh**, successfully organized the **Transfer of Technology (ToT) Conference 2026** on 4th July 2026 at the LUB Head Office, New Delhi. The

conference brought together scientists, academicians, industry leaders, innovators, and MSME entrepreneurs on a common platform to promote technology commercialization and meaningful industry-academia partnerships. Around 45 participants attended the conference physically, while approximately 35 participants joined online. The inaugural session was graced by Shri Om Prakash Gupta, National General Secretary, LUB; Shri Amit Goyal, National Coordinator - Technology Transfer, LUB; Smt. Jayanti Goela, National Coordinator - Industry Academia, LUB; Prof. Manu Sharma, Coordinator, DST-TEC, Panjab University; and Prof. Deepak Chitkara, Coordinator, DST-TEC, BITS Pilani. During the conference, twenty industry-ready technologies spanning clean energy, water treatment, agriculture, Industry 4.0, waste management, and advanced materials were showcased, opening new avenues for technology adoption and commercialization by MSMEs. The enthusiastic response from the industry was reflected in the receipt of 15 Expressions of Interest (EOIs) for the showcased technologies, and follow-up meetings with the respective technology providers and industry partners are currently underway to explore potential collaborations and technology transfer opportunities. The event reaffirmed LUB's belief that research achieves its true impact when translated into practical solutions that address industrial challenges and create value for society.

As part of its ongoing efforts to build technological capabilities among MSMEs, LUB, in collaboration with Vidyalankar Polytechnic, Mumbai, organized a two-day online workshop on **'Industry 4.0 Made Easy for MSMEs: From Concept to Implementation'** on 10-11 July 2026. Around 60 LUB members participated enthusiastically in the workshop. The sessions, conducted by Dr. Sandhya Kumar, provided practical insights into Smart Factory concepts, Digital Twin Technology, Digital Maturity Assessment, and Structured Implementation Roadmaps. The workshop enabled MSMEs to better understand the practical aspects of digital transformation and the adoption of Industry 4.0 technologies in a systematic and cost-effective manner.

Adding another landmark achievement to the month, Laghu Udyog Bharati signed a **Memorandum of Understanding (MoU)** with the **IIT Guwahati - North Eastern Science and Technology (NEST) Cluster** at Guwahati. This strategic partnership aims to strengthen industry-academia collaboration by facilitating technology transfer, industry-driven research, startup promotion, skill development, commercialization of innovations, and collaborative solutions for industrial challenges. The collaboration will focus on emerging technologies including Artificial Intelligence, Drone Technology, Bamboo Technology, Biodegradable Plastics, Nanotechnology, Wastewater Treatment, Sustainable Manufacturing, and several other frontier domains. Through this partnership, LUB members will gain access to IIT Guwahati's research expertise, innovation ecosystem, pilot projects, internship opportunities, and technology commercialization support, thereby enabling MSMEs to adopt advanced technologies, improve productivity, and enhance global competitiveness.

The initiatives undertaken during July, 2026 reflect the Industry-Academia Vertical's unwavering commitment to building meaningful partnerships between industry, academia, and research institutions. By facilitating technology transfer, promoting innovation, strengthening skill development, and accelerating the adoption of emerging technologies, Laghu Udyog Bharati continues to empower MSMEs and contribute towards building a technologically advanced, self-reliant, and globally competitive India.

❑❑❑

Roorkee conducts Successful Industry Dialogue

Report
Birendra Shukla
Distt. General Secretary
Laghu Udyog Bharati, Roorkee Nagar
lubroorkee@gmail.com

The Industry Dialogue and Felicitation Ceremony was jointly organized by the LUB's Roorkee Nagar unit and SIDCUL (Old Industrial Area) unit on July 18. Speaking on the occasion, Shri Bharat Chaudhary, the Cabinet Minister for Industries in the Uttarakhand government, stated that issues concerning industries would soon be presented to the Chief Minister, and the government would strive to resolve them.

Transport Minister UK Govt. Shri Pradeep Batra announced the imminent construction of a 'Transport Nagar' in Roorkee-Haridwar highway. Shri Kailash Melana, the State In-charge of Laghu Udyog Bharati Uttarakhand, announced the formation of new units for Bhagwanpur and Roorkee Rural areas of Haridwar district.

State President Dr. Bijay Singh Tomar hailed the event as a success, noting that it served as a vivid example of the organization's unity, dedication, and excellent work ethic.

During the program, esteemed journalists from Roorkee were honored with mementos. Dignitaries present at the event included Mayor Smt. Anita Agrawal; BJP District President-Roorkee Dr. Madhu Singh; Shri Shobharam Prajapati, Shri Deshraj Karnwal, and Shri Aadesh Saini (Ministers of State rank, Uttarakhand Govt.); Shri Uttam Tiwari General Manager, District Industries Centre; Shri Kamal Kishore Regional Manager, SIDCUL Haridwar; Dr.

Rajendra Singh (Regional Manager, Pollution Control Board; and Amit Bhardwaj Pollution Control Board, Roorkee, along with several senior administrative officials.

Office-bearers from various industrial organizations in the Haridwar district-including Shri Sukhdev Singh, Shri B.B. Gupta, Shri Ajay Garg, Shri Rakesh Mittal, Shri Shivam

Pending 6 Core Demands

- Regular meetings of the MSME Facilitation Council with CM.
- Change of Land Use (CLU) for industrial purposes should be made time-bound.
- Notices related to building tax and license fees to industrial units should be on hold.
- Industrial subsidy pending since the year 2023 should be disbursed expeditiously.
- Approval of building plans/maps for industrial units only from SIDA within time.
- The power distribution infrastructure in industrial areas should be strengthened.

Goyal, Shri Prabhat Kumar, and Shri Nikhat Rathi- were in attendance.

Representatives from Laghu Udyog Bharati, such as Shri Pradeep Khanduri, Shri Sanjay Gupta, Shri Mayank Garg, Shri Manoj Mishra, Shri V.P. Singh, Shri Ashok Shukla, Shri Praveen Garg, Shri Vinit Dhiman, Shri Aditya Tomar, Shri Sunil Pandey, Shri Piyush Mandhar, Shri Rahul Prajapati, and Shri Himanshu Walia, were also present.

The event saw participation from office-bearers of various industrial organizations- including RSSIA, BIDWA, BIA, SEWA, HIDA, and IIA-as well as senior state-level office-bearers of LUB Uttarakhand and a large number of entrepreneurs from the industrial sector. The presence of over 200 participants made the event highly successful and impactful.

Shri Manoj Gautam, District President of Laghu Udyog Bharati (SIDCUL), delivered the vote of thanks, while Shri Ketan Bhardwaj, District President of the Roorkee City unit, conducted the proceedings.

❑❑❑

Raja Shasanka Kaushal Vikash Kendra run by LUB's Madhya Bengal was inaugurated by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji at Berhampore, Murshidabad on 27th July. The centre has successfully commenced its first batch of skill development programs with 10 students enrolled in the Bakery Course, where they are receiving practical training in the preparation of biscuits, cookies, and bread. Additionally, 5 students have enrolled in the Computer Training Course, covering Tally and GST software.

Through this initiative, Laghu Udyog Bharati continues to support the Government's vision of Skill India, Atmanirbhar Bharat, and Viksit Bharat, while strengthening the MSME ecosystem through skill development, self-employment, and entrepreneurship.

LUB's News in Brief

LUB's Murshidabad District Unit (West Bengal) was inaugurated with Udyami Sammelan held at Berhampore on 24th July.

The program was graced by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji, National Vice President Shri Saroj Kumar Sahoo, local MLA, ADM, Maharaj of Sargachhi Ramakrishna Math, State Secretary Shri Debiprasad Mukhopadhyay; Sambhag President Shri Ratan Prasad Konar, Secretary Shri Arup K. Roy, the District Sangh Chalak; and entrepreneurs from across West Bengal.

Representatives from SBI, UCO Bank, ONDC, NSIC, MSME, and DIC also participated, reaffirming their commitment to promoting entrepreneurship and strengthening the MSME ecosystem in Murshidabad. The event witnessed the enthusiastic participation of nearly 500 entrepreneurs, industrialists, and stakeholders, showcasing the growing strength and unity of the MSME ecosystem in the region.

The Jalore unit of LUB's Jodhpur Anchal organized the foundation stone laying ceremony for a Skill Development Centre in the presence of Shri Prakash Chandra ji National Organizing Secretary-LUB and Shri Ganganath Maharaj of Bhairunath Ji Akhada.

LUB's National EC member Shri Shantilal Balad outlined the activities of the skill development training centres run by Laghu Udyog Bharati in Rajasthan.

Jodhpur Anchal General Secretary Shri Suresh Bishnoi stated that this modern centre, spanning an area of approximately 10,000 square feet, would provide technical, vocational, and employment-oriented training to youth and women.

During the event, Jalore-Sirohi MP Shri Lumbaram Choudhary announced a contribution of ₹21 lakh from his MP fund, while MLA and Chief Whip Shri Jogeshwar Garg announced ₹10 lakh from his MLA fund for the centre's development. Additionally, the Mining Association contributed ₹11 lakh, and the Granite Association presented a cheque for ₹5 lakh as a first instalment. All donors were welcomed and felicitated on the occasion.

The centre will feature digital classrooms, e-learning platforms, modern laboratories, a library, Wi-Fi facilities, video conferencing capabilities, and workshops. It will offer training and internships aligned with industrial needs, instruction by expert trainers, assessment and certification, as well as employment and placement services.

On the occasion, Former President Shri Ghanshyam Ojha; State General Secretary Shri Sudhir Kumar Garg; State Vice President and Jodhpur Anchal In-charge Shri Mahavir Chopra; State Jt. General Secretary Shri Vinay Bamb; Anchal President Shri Balkishan Parihar, State EC member Shri Nandkishore Radad, Anchal Secretary Shri Rajveer Singh, Anchal EC member Shri Ramniwas Bapodia, Building Construction Coordinator Shri Mahesh Mor, Bhagli Unit President Shri Aman Agarwal, and Secretary Shri Hitesh Solanki were also present.

Jalore Unit President Shri Dinesh Agrawal expressed the vote of thanks. General Secretary Shri Krishnakant Jaithaliya conducted the proceedings.

LUB's Balasore District Unit (Odisha East) was formally constituted in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji, Odisha Prabhari Shri Saroj Kumar Sahoo, State President Shri Gopal Das Agarwal, General Secretary Shri Pradip Kumar Nayak, Former President Shri Tapan Kumar Swain and Shri Saroj Kumar Senapati. Shri Shiv Kumar Poddar as President and Shri Bishnu Kumar Maroo as Secretary with nine-member Executive Committee members were nominated.

LUB's delegation led by National Organizing General Secretary Shri Prakash Chandra Ji paid a courtesy visit to the state's Chief Minister, Shri Vishnu Deo Sai, and shared detailed information about the 14th India Industrial Fair (IIF) to be held at Raipur, the capital of Chhattisgarh, on September 18, 19, and 20.

This event will enable entrepreneurs from across the country to establish new business relationships and will create opportunities for technical exchange, investment, and business expansion. The fair will prove to be a significant platform for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and will play a crucial role in establishing a stronger identity for Chhattisgarh on the national industrial map.

Appreciating this initiative, Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai expressed confidence that such a national-level event would provide fresh momentum to investment, employment, and industrial development in the state. It is a matter of pride for Chhattisgarh that a national industrial gathering of small-scale industries on such a grand scale is being organized in Raipur for the first time.

Jt. National General Secretary Shri Naresh Pareek, National Vice President Shri Sameer Mundra, State President Smt. C.P. Dubey, Shri Purushottam Patel, Shri Anil Bakliwal, Smt. Tulika Pandey, and Shri Pranjal Singh Thakur were present on this occasion.

A delegation from Laghu Udyog Bharati paid a courtesy visit to the Chief Minister of Goa Shri Dr. Pramod Sawant on 17th July. The delegation included LUB's National Organising Secretary Shri Prakash Chandra ji, National VP & Goa Prabhari Shri Sachin Sabnis, Belgaum President Shri Mahesh Inamdar, State President Pallavi Salgaocar, and General Secretary Shri Mudit Agarwaal. During the meeting, the team updated the Shri Sawant for LUB's ongoing initiatives to empower small businesses, strategic partnerships and collaborations to drive the growth of MSMEs across Goa. The delegation also presented the latest edition of 'Udyog Times'.

LUB's Delegation led by National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra Ji met Chief Secretary, West Bengal Shri Manoj Agarwal-IAS at

his residence at Kolkata and held detailed discussions on the industrialization of the state and the overall development of the MSME sector.

The meeting deliberated on a strategic roadmap for the state's industrial development. Key topics included MSME and cluster development, budgetary policies, industrial land bank, development of rural and urban infrastructure, skill development for local youth, and entrepreneurship promotion programs.

During the meeting, Shri Prakash Chandra Ji particularly emphasized the development of the jute industry and the engineering sector, stating that providing incentives to these sectors could impart new momentum to West Bengal's industrial prosperity. He also stressed the need to develop favourable policies for MSMEs in the state and a robust industrial ecosystem.

The delegation expressed its commitment to working together with the state government to enhance coordination, foster industrial development, create employment, and empower local entrepreneurship.

On this occasion, the delegation also included National Vice President Shri Saroj Kumar Sahoo, National EC Member Shri Paul Kumar Mitra, President South Sambhag Shri K.K. Sekhsaria, and General Secretary Shri R.K. Shobhasaria.

A significant MOU was signed between the Laghu Udyog Bharati (LUB) and Indian Institute of Architects (IIA) for organizing the 23rd ARCASIA Forum-2026 at Jaipur on 11th July.

One of Asia's premier architectural conferences, the ARCASIA Forum is scheduled on September 11-12, across Delhi, Agra, and Jaipur. The MoU was signed by Shri Naresh Pareek, National Jt. General Secretary LUB, and Architect Tushar Sogani, Convener of the 23rd ARCASIA Forum-2026, representing the Indian Institute of Architects.

The forum, themed 'Bringing Back... Vernacular Wisdom,' will see the participation of approximately 3,500 delegates from over 24 countries. By recognizing Laghu Udyog Bharati as the forum's 'Industrial Partner,' the event will facilitate networking opportunities at both national and international levels.

On the occasion, LUB's former National President Shri Ghanshyam Ojha, former National Treasurer Shri (CA) Yogesh Gautam, Rajasthan General Secretary Shri Sudhir Garg, Vice President Shri Natwar Lal Ajmera, Jaipur Anchal President Shri Mahendra Mishra, and Jodhpur Anchal General Secretary Shri Suresh Bishnoi; as well as IIA Vice President Ar. Gaurav Agarwal, Jt. Secretary Ar. Prakash Mohanani, Ar. Ashutosh Bhargava, and member Ar. Nishtha Pandey were also present.

LUB's Belagavi Women's Wing (Karnataka) organized a special program to train women entrepreneurs in the art and craft of handmade products. State Vice President Dr. Priya Puranik stated that, National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji called upon the entrepreneurs to tackle the challenges facing their industries through collective effort and cooperation. Belagavi President Smt. Nalini Vemulkar presented a detailed report on the activities planned for the 2023-2026 period. Notably, these programs include educational and public awareness initiatives, as well as training in areas such as digital awareness, eco-friendly bag making, and pottery. The proceedings were conducted by Women's Wing Secretary Smt. Lata Hooli, while Smt. Ashwini Belgavkar proposed the vote of thanks.

During a visit to Agra, a delegation from LUB met with the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, in the presence of MSME Minister Shri Bhupendra Chaudhary and Agra MP Prof. S.P. Singh Baghel. Meaningful discussions took place regarding the state's industrial development, the expansion of the MSME sector, and various key issues concerning entrepreneurs. Several entrepreneurs, including National Joint General Secretary Shri Rakesh Garg, State Secretary Shri Manish Agarwal, and Agra District President Shri Vijay Gupta, were also present on the occasion.

The state executive meeting of Laghu Udyog Bharati, Madhya Pradesh, was held at 'Udyam Setu' Bhopal on 26th July. During the first session, the skill center was inaugurated, and guidance was provided on strengthening the organization. In the second session, plans for organizational expansion and upcoming programs were formulated through zone-wise group meetings. The third session featured presentations on various topics- including ITI-related activities, technology transfer, and Utpad Samuh- followed by a detailed review of the future action plan. Special discussions were held regarding preparations for 'Udyam Samagam-2026' scheduled to take place in Indore on 3rd October, 2026. Presided over by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji, the meeting was attended by National Vice President and Madhya Pradesh In-charge Shri Tarachand Goyal, former National President Shri Jitendra Gupt, former National Vice President Dr. Ajay Narang, State President Shri Rajesh Mishra, State GS Shri Arun Soni, National Media In-charge Shri Ateet Agrawal, and office bearers from various anchals.

LUB's Goa state unit in association with World Trade Center, Global Chamber Goa, and Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), organised an International Seminar on "Dubai - The Business Gateway to Global Trade" on 23rd July at Panaji.

The program aimed to create awareness among MSMEs, entrepreneurs, exporters, and business professionals about global trade opportunities and the advantages of expanding business operations through Dubai. The seminar highlighted the strategic role of DMCC as a leading international business hub connecting Indian enterprises to global markets.

The inaugural session featured addresses by Shri Cyril D'Souza, Regional Director - Trade Promotion, WTC Goa; Smt. Pallavi Salgaocar, LUB's State President, Shri Gautam Kharangate, Director & CEO, Rashtra TV and Shri Arman Bankley, Trustee-Vibrant Goa Foundation, who highlighted the importance of export readiness, international collaboration, and strengthening MSMEs through global partnerships. The technical session was led by Shri Abhijitsinh Jadeja, Chief Representative - India Office, Asia

Region, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), and Shri Siddharth Shah, Founder & CEO, MARC Global, who shared valuable insights on setting up businesses in Dubai, trade facilitation services, and the opportunities available for Indian MSMEs to access international markets. A Knowledge Report on the India-UAE Business Environment was also released.

LUB's Punjab State unit organized its 8th Foundation Day celebration and State EC meeting in the special presence of the Governor Shri Gulab Chand Kataria and LUB's National President Shri Madhusudan Dadu, at Mongia & Company, Dera Bassi on 11th July.

Addressing the event, Shri Kataria stated that MSMEs are the backbone of the Indian economy and play a crucial role in providing approximately 60 percent of the country's employment.

The event saw the active participation of LUB's National VP Shri Arvind Dhumal, National Secretaries Smt. Anju Bajaj and Smt. Anju Singh, Shri Shubhadesh Mittal, Punjab State President Shri Pradeep Mongia, General Secretary Shri Vivek Rathore, Jt. GS Shri Anil Sharma, Jt. Treasurer Shri Suresh Gupta, and Joint Secretary Shri Devendra Kaushal, alongside Dera Bassi Unit President Shri Rahul Gupta, General Secretary Shri Deepak Dhingra, and Treasurer Shri Vikas Grover. Representatives from the Punjab Women's Wing included Smt. Seema Dhumal, Smt. Amandeep Shergill, Smt. Mona Mongia, and Smt. Priyanka Goyal, while Smt. Komal Dhingra, Smt. Khushbu Verma, Smt. Shahina Gupta, and Smt. Ira Mongia actively participated on behalf of the Dera Bassi Women's Wing.

LUB's Chittor Prant (Rajasthan) meeting was concluded in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, Former National President Shri Ghanshyam Ojha, State GS Shri Sudhir Garg, Prant President Shri Mahesh Hurkat and Prant GS Shri Praveen Gupta at Kishangarh on 20th July.

During the meeting, the organizational achievements of the past year were reviewed, and detailed discussions were held on the action plan for the upcoming year. Key topics included membership expansion, the establishment of skill development centers, the 'Swayamsiddha' Exhibition to promote women's entrepreneurship, business growth via the LEAP portal, and events such as Stonemart and the West Rajasthan Industrial Fair. Committees were formed to address issues related to industry, electricity, mining, the environment, and RIICO, and views were also expressed regarding the vital role of industries in nation-building. The participation was observed more than 170 entrepreneurs and organization office-bearers from various districts of the state.

As part of the 15th BRICS Trade Union Forum Summit-2026, under India's BRICS Chairship and hosted by the Bharatiya Mazdoor Sangh, LUB Telangana actively participated in deliberations focused on labour, employment, and inclusive economic growth at Hyderabad on 14-16 July.
Telangana State President Shri Vasantham Venkateswarlu addressed the international gathering and emphasized that India's growth story must focus not only on generating employment but also on creating quality, secure, and dignified jobs for the workforce. He briefed delegates on LUB's nationwide initiatives promoting MSME development, skill enhancement, employee welfare, industrial harmony, entrepreneurship, and social responsibility. On this occasion, Telangana State General Secretary Shri K. Narendra Nath Dutt, Vice President Shri Sudhakar Sharma and Secretary Shri Kusuma Venkatesh were also present.

LUB's Belagavi Unit of Karnataka, in association with the Quality Council of India (QCI) and supported by SIDBI, organized a "ZED (Zero Defect Zero Effect) Certification Awareness Program" at Belagavi.
The event drew 127 local MSME participants looking to adopt global quality standards, learn about financial incentives, and explore banking support. Shri Prakash Chandra ji-National Organizing Secretary and Dr. Sachin Sabnis National Vice President-LUB, Shri Bharat B. Deputy Director-DIC, Shri Pramod Paranjape Senior Manager-RSJ Inspection Service and Shri Sachanand Mohnani-AGM, SIDBI.

A Margdarshan Program was held at Itanagar by Executive Member Laghu Udyog Bharati Arunachal Pradesh Unit to seek the guidance of Shri Kamlesh for strengthening the organisation and its future initiatives.

An important meeting was organised by LUB's Uttar Pradesh for detailed discussions on local administrative and industrial challenges, and legitimate suggestions for their resolution at Kasgunj on 12th July. LUB's National Jt. GS and Chairman of Uttar Pradesh Small Industries Corporation Limited, Shri Rakesh Garg, TTJ Authority member Shri Vijay Gupta and Shri Braj Sambhag General Secretary Shri Amalendu and District President of Etawah were present.

The approval of the National Investment Policy for Urea–2026 (NIPU-2026) will boost domestic urea production, reduce import dependence, strengthen fertilizer security, and ensure timely availability for farmers. The policy will also create significant opportunities for MSMEs in engineering, fabrication, industrial equipment, EPC, logistics, and allied sectors. A strong step towards empowering both farmers and Indian manufacturing.

A meeting of the LUB Uttar Pradesh Women's Wing was held under the guidance of State Vice President & State Convener (Women Work) Smt. Rita Mittal at Lucknow on 15th July. Discussions during the meeting focused on an action plan for the next three months, covering areas such as women's entrepreneurship, organizational expansion, and networking programs.

A LUB delegation led by the Rajasthan State General Secretary, Shri Sudhir Garg, met with Smt. Anila Mem, Dy. Director- Small-Scale Industries, GoI at Sikar to discuss skill development, the 'Swayamsiddha' initiative, and the Zila Udyami Sammelan on 20th July. Ms. Sunita Sharma-GS Jaipur Anchal & Smt. Ritu Agarwal Jt. GS, Smt. Vaishali Vashishth-President Jagatpura Women's Unit, Sikar unit President Shri Harishankar Agrawal, Secretary Shri Krishna Kumar Purohit, and Treasurer Shri Ramavatar Agrawal were also present on this occasion.

The Women's Wing of Laghu Udyog Bharati, Katni (MP), planted 100 saplings at the Dayoday Pashu Seva Kendra (Gaushala) in Kailwara.

With the aim of strengthening the textile industry and addressing future challenges, Laghu Udyog Bharati announced the formation of a national-level 'Textile Committee' at Surat on 14th July. Shri Mahesh Hurkat, head-Textile Utpad Samuh, stated that a national meeting would be held at New Delhi on October 1. During this meeting, comprehensive discussions regarding 'Textile Vision-2047' will take place with Union Ministers and senior officials from the Ministry of Commerce and Textiles. LUB's Surat President Shri Ramavatar Pareek, GS Shri Satish Savani, VP Shri Ramesh Rathi, Jt. GS Shri Pankaj Sharma, Treasurer Shri Vinod Saraswat and FOSTA VP Shri Hansraj Jain were present.

LUB's UP General Secretary Shri Rajesh Singh addressed the students on the World Youth Skills Day at Varanasi on 15th July.

LUB's North Bengal unit initiated Industrial Visit for the school students to develop entrepreneurial temperament in young generation.

The 'Swayamsiddha' Exhibition organized by the Jodhpur Women's Wing of Laghu Udyog Bharati on July 25–26, was inaugurated by District Collector Shri Alok Ranjan and Additional Deputy Commissioner of Police (Traffic) Shalini Raj. The exhibition featured stalls showcasing various products from home-based industries, including handicrafts, textiles, healthcare, food and beverages, and home furnishings. Shri Ghanshyam Ojha, former National President of Laghu Udyog Bharati, encouraged the women entrepreneurs.

LUB's delegation met Shri Manjinder Singh Sirsa Industry Minister, Govt. of Delhi for resolution of long-awaited issues concerning the Okhla Industrial Area. Delhi State President Shri Diwan Chand Gupta, General Secretary Smt. Arti Sehgal, leading industrialist Shri Rakesh Bansal, Shri Arun Sareen, and Shri Vijay Dhawan were present at Delhi Secretariat on 26th July.

LUB's Alipurduar District unit President Shri Jagdish Madiya met Minister of MSME Shri Deepak Burman, Govt. of West Bengal to discuss the issues concerning the MSMEs.

LUB's South Sambhag of West Bengal and Akhil Bhartiya Swarnkar Vikash Parishad jointly organised an Export Training Program for Gold Jewellery Sector; supported by MSME dept. Govt of India. On the completion of training, 29 entrepreneurs received the certificates on 8th July. At this juncture, Shri Samik Bhattacharjee, President West Bengal, BJP assured the full support to revitalise the large and MSME industries of West Bengal. Shri Saroj Kumar Sahoo-National Vice President, Shri K. K. Seksaria-President-South Sambhag, Shri Ramesh Sovasaria-General Secretary, Shri Vijay Agarwal-Past President, Shri Bateswar Jha-Vice President, Senior officials of MSME and NSIC were also present.

A 'Mega Industrial Promotion Camp and Awareness Workshop' for micro and small industries was organized under the joint aegis of the LUB's Jodhpur Prant and the Rajasthan Financial Corporation, in the presence of LUB's former National President Shri Ghanshyam Ojha, Jodhpur Prant Prabhari Shri Mahavir Chopra, General Secretary Shri Suresh Bishnoi and RFC Executive Director Shri Harsahay Meena on 8th July.

LUB's Agar unit (MP) organized a Tree Plantation Drive and an Industrial Workshop at the new industrial estate.

LUB's Kerala State unit marks International MSME Day with strategic discussion on MSME ecosystem and strengthening local enterprises. A constructive meeting was held in the presence of Tripunithura Municipal Corporation Chairman Shri. Adv. P. L. Babu, LUB's State VP Shri Venkateswaran Sitaraman and President Ernakulam District Smt. Dharmaja Menon at Tripunithura on 4th July.

LUB's Harda unit (MP) organized an inspiring session for first-year students at the Govt. Polytechnic College as part of its 'Successful Entrepreneur Series' on 30th July. President Shri Abhay Jain and Secretary Shri Rajesh Agarwal interacted with the students, fostering a spirit of self-employment, innovation, self-confidence, skill development, and self-reliance among them.

LUB's Bikaner unit conveyed a message of environmental conservation by planting 200 saplings in the Karni Industrial Area. On the occasion, Prof. Akhil Ranjan Garg-Vice-Chancellor, Bikaner Technical University, Shri Balkishan Parihar-President, LUB Jodhpur Prant, and former unit President Shri Harsh Kansal, Shri Rajesh Goyal, and Shri Vinod Dhanuka, along with other entrepreneurs.

LUB's Purnia (Bihar), unit conducted an Udyami Sammelan in the presence of Shri Suresh Rungta- Chairman, Bihar State Entrepreneurs and Business Commission), Shri Shyamsundar Bhimseria-State President, Shri Shivshankar Prasad Sahu-Vice President, and Shri Suman Shekhar-National EC Member. During the program, the President briefed on discussions held with the Chief Minister regarding freehold status, facilitation charges, the state procurement policy, and land allotment policy. The organization expressed its gratitude to the government for the 'Ease of Doing Business Bill'.

A high-level coordination meeting was held between State Bank of India, National Small Industries Corporation (NSIC), and Laghu Udyog Bharati to discuss a joint initiative for organizing MSME finance and entrepreneurship programs at Berhampore and Kolkata under the banner of 'Mission ₹100 Crore Spot Sanction' on 10th July. The meeting was attended by Shri Saroj Kumar Sahoo, National VP-LUB, Shri Ramesh Sovasaria, General Secretary, South Sambhag, Shri Ratan Agarwal-Acting President, Modhya Bongo, Shri Surya Narayan Panigrahi GM-SBI, Shri Shams Tabrez-Dy. General Manager (SME)-SBI, Dr. Anupam Gayan-Zonal GM-NSIC, Shri Bipul Bag-Sr. Manager-NSIC and other senior officials.

LUB's Purvottar Women Wing cordially invites all members to participate in the 3rd Edition of Swayamsiddha Exhibition and showcase their products and entrepreneurial spirit on 31st October-1st November. Such kind of active participation and support will play a vital role in making this event a grand success.

The first consignment under the LUB Purvottar Flood Relief Initiative was flagged off from Chandmari, Guwahati. The relief materials will be distributed in the flood-affected areas by LUB's Golaghat and Jorhat units.

LUB's Ayurveda unit held a detailed discussion related to stability reports on the e-Aushadhi portal, the latest gazette notification, and the industry's current challenges and their solutions at Jaipur on 31st July.

The Bhilwara Women's Wing of LUB launched the 'Digital Sakhi' program to digitally empower women entrepreneurs. Under this initiative, women will receive training on digital literacy & marketing, social media usage, financial literacy, GST, digital payments, online business management, and government schemes. Dr. Priyanka Mehta-Secretary, Smt. Priya Kothari, Smt. Rekha Inani, Smt. Asha Somani, and Smt. Sarita Agarwal collaborated on this initiative.

LUB's Chandigarh President Shri Avi Bhasin met Governor cum Administrator Punjab & Chandigarh Shri Gulab Chand Kataria to pursue long-pending policy matters related to MSMEs on 30th July.

A delegation from LUB's Kala-Amb unit met the Governor of Himachal Pradesh, Shri Kavinder Gupta, on July 30. Unit President Shri Akhil Maheshwari stated that they apprised him of the industrial area's development, various industry-related matters, and key issues facing the region.

LUB's Puducherry delegation met Union Minister MSME Shri Jitan Ram Manjhi to discuss the growth and development of the MSME sector in the region.

Goa, a Model of

Sustainable Waste Management

State-of-the-Art
Waste Management Facilities

- Integrated Solid Waste Management Facility, Saligao
- Integrated Solid Waste Management Facility, Cacora
- Common Bio-Medical Waste Treatment Facility, Kundaim
- Common Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility (CHWTSDF) at Pissurlem
- Integrated Waste Management plants designed to generate over 400 kW of power

Issued by:
Department of Information and Publicity
Government of Goa

VIKSIT BHARAT VIKSIT GOA 2047

UDYOG TIMES
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI
30 July - 2026
Registration No. RAJBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी जी

के द्वारा राजस्थान को दी गई

1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक की अभूतपूर्व सौगातों

के लिए

आभार

₹79 हजार करोड़ से अधिक की लागत से तैयार राजस्थान रिफाइनरी का राष्ट्र को समर्पण

₹13 हजार करोड़ से अधिक लागत की जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास

जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन

यमुना जल परियोजना के लिए MoA
किशाऊ बहुउद्देशीय बाँध परियोजना से वर्ष पर्यन्त यमुना जल की उपलब्धता

ऊर्जा, सड़क एवं रेलवे की विकास परियोजनाएं | 7 कार्य | 13 हजार 443 करोड़ रुपए

राजस्थान संवाद

53,977 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र

जिला	अभ्यर्थियों की संख्या
अजमेर	1121
अलवर	2037
बालोतरा	435
बांसवाड़ा	1648
बारां	947
बाड़मेर	1116
ब्यावर	513
भरतपुर	1730
भीलवाड़ा	1199
बीकानेर	1728

जिला	अभ्यर्थियों की संख्या
बूंदी	1080
चित्तौड़गढ़	600
चूरू	1671
दौसा	2405
डीग	592
धौलपुर	864
डीडवाना-कुचामन	1480
डूंगरपुर	1709
हनुमानगढ़	1748
जयपुर	5852

जिला	अभ्यर्थियों की संख्या
जैसलमेर	461
जालौर	593
झालावाड़	842
झुंझुनूं	1695
जोधपुर	1971
करौली	1560
खैरथल-तिजारा	381
कोटा	1209
कोटपूतली-बहरोड़	951
नागौर	2051

जिला	अभ्यर्थियों की संख्या
पाली	766
फलोदी	359
प्रतापगढ़	898
राजसमंद	402
सलूम्बर	342
सवाईमाधोपुर	1482
सीकर	2505
सिरोही	488
श्रीगंगानगर	1206
टोंक	1661
उदयपुर	1679

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

Follow us
lubindia
@lubBharat
laghu-udyog-bharati
lubindia
lub.india

LUB's Monthly Magazine Published by Madhu Sudan Dadu Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019